वर्ष : 34 | अंक : 369 | मुंबई, बुधवार, 18 मार्च 2026 | RNI: MAHHIN/49994/91 | मूल्य : 3 रुपए | epaper.dobajedopahar.com | संपादक : अरुण लाल | संरक्षक : एन. के. पुरोहित

DBD
दो बजे दोपहर
पत्रकारिता पावर नहीं रिस्पांसिबिलिटी है

- उद्धव गुट के समर्थन से पास हुआ धर्मांतरण विरोधी बिल
- अब बस राज्यपाल की मुहर का इंतजार

धर्मांतरण के खेल पर नकेल

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र में जबरन और प्रलोभन के जरिए होने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए लाया गया 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026' अब कानून बनने की आखिरी दहलीज पर है। मंगलवार, 17 मार्च 2026 को गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने इसे विधान परिषद में पेश किया। विधानसभा में पहले ही पारित हो चुके इस बिल को लेकर सदन में तीखी बहस और नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिले। तीखी बहस के बाद, विधान परिषद में धर्म की स्वतंत्रता विधेयक पारित हो गया।

7 साल की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान

नए कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति प्रलोभन (लालच), बल प्रयोग या धोखाधड़ी से किसी का धर्म परिवर्तन कराता है, तो उसे 7 साल तक की कैद और 1 लाख जुर्माना भुगतना होगा। यदि मामला नाबालिगों, अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) से जुड़ा है, तो जुर्माना 5 लाख तक हो सकता है।

सामूहिक धर्मांतरण पर 10 साल की जेल

कानून में 'सामूहिक धर्मांतरण' (Mass Conversion) और बार-बार अपराध करने वालों के लिए और भी सख्त प्रावधान हैं। ऐसे मामलों में 10 साल की सजा दी जा सकती है। साथ ही, यदि किसी का धर्मांतरण केवल शादी के उद्देश्य से धोखे से कराया गया है, तो वह विवाह अपने आप अमान्य (अवैध) माना जाएगा।

विपक्ष में फूट

इस बिल ने विपक्ष की एकता को हिलाकर रख दिया है। जहाँ कांग्रेस और शरद पवार गुट (जितेंद्र आव्हाड, रईस शेख) ने इसे असंवैधानिक बताया, वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) ने इसका समर्थन किया। अनिल परब ने विधान परिषद में साफ कहा कि राज्य में बढ़ते जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए यह कानून जरूरी है। इस समर्थन के लिए भाजपा के चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे का आभार भी जताया।

सदन में हंगामा और खेद

विधानसभा में चर्चा के दौरान राकांपा नेता जितेंद्र आव्हाड की एक टिप्पणी पर इतना हंगामा हुआ कि सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। बाद में अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के निर्देश पर आव्हाड को अपने शब्द वापस लेने पड़े और उन्होंने खेद व्यक्त किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र देश का 13वां राज्य होगा जहाँ यह कानून लागू होने जा रहा है। उन्होंने डॉ. नीलम गो*हे द्वारा 2004 में मेलघाट के आदिवासियों के लिए उठाई गई आवाज का जिक्र करते हुए कहा कि दो दशक पुराने इस मुद्दे को अब कानूनी सुरक्षा कवच मिल रहा है।

ब्रीफ न्यूज़

सावरकर पर टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की राहुल को चेतावनी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर पर उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर फटकार लगाई। नवंबर 2022 में राहुल गांधी ने अपनी 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान महाराष्ट्र के अकोला में एक रैली में सावरकर के बारे में कथित रूप से मानहानिकारक टिप्पणी की थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने राहुल गांधी से 'गैर-जिम्मेदार बयान' देने से बचने को कहा और यह भी कहा कि वह स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कुछ भी न बोलें। बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा, क्या महात्मा गांधी भी वायसराय को संबोधित करते समय 'आपका आज्ञाकारी सेवक' लिखते थे? इससे कोई सेवक नहीं बन जाता।

पीएनजी कनेक्शन को 24 घंटे में मंजूरी मिलेगी

नई दिल्ली। देश में गैस की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एलपीजी सिलेंडर पर लोगों की निर्भरता घटाने के मकसद से अब पाइपलाइन गैस (पीएनजी) के विस्तार को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी कड़ी में राज्य सरकारों को यह निर्देश दिए गए हैं कि नए पाइपलाइन कनेक्शन के लिए आने वाले सभी आवेदनों पर 24 घंटे के अंदर स्वीकृति दी जाए। वहीं, जो मामले लंबित हैं, उन्हें शीघ्र अति शीघ्र सुलझाया जाए। सरकार की ओर से यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि पाइपलाइन बिछाने के कार्य के दौरान वसूले जाने वाले सड़क पुनर्निर्माण शुल्क (रोड रेस्टोरेशन चार्ज) को समाप्त किया जाए, जिससे कार्य में गति आ सके।

अपने ही देश के लोगों का दमन कर रहा पाकिस्तान : भारत

संयुक्त राष्ट्र। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान अपने ही देश के लोगों का दमन कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने अहमदिया समुदार पर जुल्म और अफगानिस्तान पर हमले को लेकर पाक को लताड़ लगाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने सवाल किया कि इस्लामाबाद द्वारा अपने ही देश में अहमदिया समुदाय के क्रूर दमन तथा रमजान के दौरान अफगानिस्तान पर किए गए हवाई हमलों को क्या नाम दिया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत पर्वथानेनी हरीश ने कहा इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) ने भारत के खिलाफ बार-बार झूठे और निराधार आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान इसका उपयोग लगातार भारत के खिलाफ हथियार के रूप में करने की कोशिश करता है।

महाराष्ट्र में ड्रग माफियाओं की खैर नहीं

अब नहीं 'उड़ेगा' महाराष्ट्र

- नशे के सौदागरों की संपत्ति ज़ब्त होगी और अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर
- पुलिसवालों की मिलीभगत पर सीधे होगी बर्खास्तगी
- ड्रग्स के खिलाफ 'ज़ीरो टॉलरेंस' पॉलिसी लागू करेंगे: देवेंद्र फडणवीस

धीरज सिंह | मुंबई

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार, 17 मार्च 2026 को विधानसभा में नशीली दवाओं (ड्रग्स) के खिलाफ आर-पार की जंग का ऐलान किया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब केवल छोटे-मोटे तस्करों पर ही नहीं, बल्कि ड्रग्स के पूरे सिंडिकेट और उसे संरक्षण देने वालों पर भी कड़ा प्रहार होगा।मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि ड्रग्स के मामलों में अब कोई रियायत नहीं दी जाएगी। आरोपितों की पहचान कर न केवल उन्हें जेल भेजा जाएगा, बल्कि उनकी अवैध संपत्ति भी ज़ब्त की जाएगी। यदि उनके घर या ठिकाने अवैध पाए जाते हैं, तो नगर निगम के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उन पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है।

'ऑपरेशन थंडर' और नागपुर का मॉडल

नागपुर पुलिस की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 11 महीनों में 'ऑपरेशन थंडर' के तहत 907 अपराध पकड़े गए हैं। इस दौरान 1254 किलोग्राम नशीले पदार्थ ज़ब्त किए गए, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कीमत 10 करोड़ रुपये के करीब है। यह अभियान अब पूरे प्रदेश में और भी आक्रामक तरीके से चलाया जाएगा।

पुलिसवालों के लिए 'नो सस्पेंशन, सीधा टर्मिनेशन'

ड्रग्स के काले कारोबार में यदि कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल पाया जाता है, तो उस पर रहम नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के बजाय सीधे नौकरी से बर्खास्त (Dis-missal) किया जाए। साथ ही, इलाके में ड्रग्स बिकने पर संबंधित पुलिस अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा।

कानून में बदलाव का प्रस्ताव

ड्रग तस्कर अक्सर कार्रवाई से बचने के लिए नाबालिगों का सहारा लेते हैं। इस पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार केंद्र को एक प्रस्ताव भेजने वाली है। इसमें मांग की जाएगी कि ड्रग्स से जुड़े गंभीर अपराधों के लिए कानूनी उम्र सीमा 18 से घटाकर 16 साल कर दी जाए, ताकि कम उम्र के अपराधियों को भी सख्त सजा मिल सके।

एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) का विस्तार

31 अगस्त 2023 को बनी एएनटीएफ को अब राज्य के हर पुलिस स्टेशन तक बढ़ाया जा रहा है। सरकार का फोकस केवल ड्रग्स पकड़ने पर नहीं, बल्कि इसकी पूरी 'सप्लाई चेन' को खत्म करने पर है। दूसरे राज्यों और केंद्र सरकार के साथ मिलकर 'इंटेलिजेंस शेयरिंग' के जरिए अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है।

फडणवीस सरकार का 'पावरफुल' फैसला

- महाराष्ट्र में 5 साल तक 'नो शॉक', बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाएगी सरकार
- दिन में बिजली इस्तेमाल करने पर 25% की छूट

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के मध्यमवर्गीय परिवारों, किसानों और उद्योगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी घोषणा की है। मंगलवार को विधान सभा में उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की मजबूत प्लानिंग के चलते अगले पांच वर्षों तक बिजली की दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि अगले पांच साल तक बिजली की कीमतों को नियंत्रित रखा जाएगा। बढ़ती महंगाई के बीच यह आम जनता और उद्योगों के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच है। सरकार का तर्क है कि बिजली उत्पादन और सप्लाई की व्यवस्था अब इतनी मजबूत हो गई है कि दरों को स्थिर रखा जा सकता है।

दिन में बिजली का उपयोग और 25% डिस्काउंट

सरकार ने सौर ऊर्जा और दिन में बिजली की बेहतर उपलब्धता का लाभ सीधे उपभोक्ताओं को देने का फैसला किया है। अब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच बिजली इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को बिल में 25 फीसदी की छूट मिलेगी। यह कदम लोगों को दिन में बिजली इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

डेटा सेंटर सेक्टर के लिए 'पावर' प्लान

महाराष्ट्र तेजी से डिजिटल हब बन रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आने वाले डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स के लिए 4,500 मेगावॉट बिजली देने की तैयारी है। स्थिर और सस्ती बिजली मिलने से आईटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में महाराष्ट्र की पकड़ और मजबूत होगी। राज्य में उद्योगों के विस्तार के कारण बिजली की खपत में 23 परसेंट का उछाल आया है। फडणवीस ने कहा कि दूसरे राज्यों के मुकाबले महाराष्ट्र में बिजली के रेट आज भी काफी कॉम्पिटिटिव (किफायती) हैं, जिससे नए निवेश के रास्ते खुले हैं।

मुख्यमंत्री का हाई-टेक सुरक्षा विजन

- राज्य को अपराधमुक्त और 'स्मार्ट सुरक्षा' से लैस करने के लिए एक आधुनिक रोडमैप तैयार
- सीसीटीवी नेटवर्क से बनेगा भयमुक्त महाराष्ट्र

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य को अपराधमुक्त और 'स्मार्ट सुरक्षा' से लैस करने के लिए एक आधुनिक रोडमैप तैयार किया है। मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य की सुरक्षा केवल पुलिस बल पर नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ड्रोन तकनीक पर आधारित होगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि पूरे राज्य में लगे सीसीटीवी कैमरों को केवल 'रिकॉर्डिंग' तक सीमित न रखकर उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा जाए।

इसके प्रभावी संचालन के लिए एक नए महामंडल की स्थापना की जाएगी। खास बात यह है कि अब पुलिस जांच में शहरों में लगे निजी सीसीटीवी (Private CCTV) के डेटा का भी उपयोग किया जा सकेगा, जिससे सुरक्षा घेरा और मजबूत होगा।

'म्यूजिक' महामंडल की स्थापना

तकनीक के क्षेत्र में महाराष्ट्र को अग्रणी बनाने के लिए 'महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन' (MUSIC) नामक संस्था बनाई जाएगी। यह संस्था ड्रोन और स्वचालित तकनीकों का सरकारी कामकाज में उपयोग सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री का मानना है कि इससे मानवीय दखल कम होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।

जहाँ एक तरफ ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल निगरानी के लिए होगा, वहीं इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त 'ड्रोन नीति' भी तैयार की जा रही है। फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नई नीति में इस बात का ध्यान रखा जाए कि ड्रोन का गलत इस्तेमाल सुरक्षा के लिए खतरा न बने।शहरों में सुरक्षा की निगरानी के लिए सेंट्रलाइज्ड कमांड सेंटर बनाए जाएंगे। ये सेंटर न केवल पुलिसिंग के लिए बल्कि ट्रैफिक कंट्रोल और आपातकालीन सेवाओं के लिए भी 'नर्व सेंटर' का काम करेंगे। इसमें प्राइवेट सेक्टर के विशेषज्ञों की मदद भी ली जाएगी ताकि तकनीकी खामियां न रहें।

सेल्फ फाइनेंस स्कूल विधेयक पारित

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

विधानसभा में मंगलवार को भारी बहस के बीच 'सेल्फ फाइनेंस स्कूल (संशोधन) विधेयक 2026' ध्वनिमत से पारित हो गया, जिसके तहत अब राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं भी राज्य में स्कूल खोल सकेंगी और मौजूदा संस्थानों को कक्षा 1 से 12वीं तक विस्तार की अनुमति होगी। शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने स्पष्ट किया कि इस कानून का उद्देश्य शिक्षा में पारदर्शिता लाना और बुनियादी सुविधाओं को अनिवार्य बनाना है, साथ ही अचानक स्कूल बंद करने वाले प्रबंधन पर दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, विपक्ष ने इसे शिक्षा के निजीकरण की कोशिश बताते हुए पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण न होने पर कड़ा ऐतराज जताया, जिस पर सरकार ने दलील दी कि ये स्कूल एक अलग कानूनी ढांचे में आते हैं लेकिन आरटीई (RTE) के तहत 25% सीटें आरक्षित बनी रहेंगी।

वीजा खत्म होने के बाद रुकने वाले नपेंगे

अवैध विदेशी नागरिकों पर फडणवीस का हंटर

- लागू होगा डायनामिक इमिग्रेशन सिस्टम

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों और उनके जरिए फैल रहे ड्रग्स के जाल को खत्म करने के लिए 'डायनामिक इमिग्रेशन सिस्टम' का ऐलान किया है। मंगलवार, 17 मार्च 2026 को विधानसभा में उन्होंने साफ किया कि अब विदेशी नागरिक वीजा खत्म होने के बाद 'कानूनी पैंतरे'बाजी कर भारत में नहीं रुक पाएंगे। मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि कई विदेशी नागरिक (विशेषकर नाइजीरियाई) पढ़ाई या इलाज के नाम पर आते हैं और वीजा खत्म होने पर जानबूझकर छोटा-मोटा जुर्म कर लेते हैं। कानूनन, केस पेंडिंग होने तक उन्हें डिपोर्ट नहीं किया जा सकता था। अब केंद्र के सहयोग से ऐसे छोटे केस वापस लेकर उन्हें तुरंत डिपोर्ट (देश निकाला) करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब तक 68 को भेजा जा चुका है और 122 डिटेंशन सेंटर में हैं।

मकान मालिकों के लिए सख्त चेतावनी

सरकार ने आदेश दिया है कि बिना वैध पासपोर्ट और वीजा वाले किसी भी विदेशी को घर किराये पर न दिया जाए। यदि कोई मकान मालिक अवैध नागरिक को पनाह देता पाया गया, तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।

पुलिस और इमिग्रेशन का 'डिजिटल गठजोड़'

अब मुंबई आने वाले हर विदेशी नागरिक का डेटा पुलिस और इमिग्रेशन विभाग के बीच साझा होगा। 'डायनामिक इमिग्रेशन सिस्टम' के जरिए पुलिस को तुरंत पता चल जाएगा कि किसका वीजा किस दिन खत्म हो रहा है। अगर कोई बिना वैध दस्तावेजों के मिला, तो उसे सीधे डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा।

'मकोका' और लाइसेंस कैंसिलेशन

ड्रग्स तस्करी में शामिल आदतन अपराधियों के खिलाफ अब 'मकोका' जैसी कठोर धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। जिन कैफे या होटलों में ड्रग्स का इस्तेमाल पाया जाएगा, वहां न केवल छापेमारी होगी बल्कि उनके लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द करने के लिए कानून में बदलाव किया जा रहा है।

विधानसभा प्रश्नोत्तर | मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों पर सुस्ती

12 साल में 136 सिफारिशें, आधी अब भी फाइलों में कैद

- विधायक अतुल भातखलकर ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों पर अमल में हो रही देरी का मुद्दा मंगलवार को विधानसभा में गरमाया रहा। दिलचस्प बात यह रही कि सत्ता पक्ष के ही विधायक अतुल भातखलकर ने इस मुद्दे पर अपनी ही सरकार से तीखे सवाल पूछे। उन्होंने मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में पीड़ितों को न्याय और मुआवजा मिलने में होने वाली लेटलतीफी पर गहरी चिंता जताई। राज्य मानवाधिकार आयोग ने पिछले 12 वर्षों में कुल 136 सिफारिशें सरकार को भेजी थीं। इनमें से आधे से ज्यादा मामले लंबे समय तक ठंडे बस्ते में पड़े रहे। विधायक भातखलकर का मुख्य आरोप यही था कि जब आयोग बार-बार निर्देश दे रहा है, तो प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है?

हाईकोर्ट की फटकार के बाद जागी सरकार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन को आंकड़ों के जरिए स्थिति स्पष्ट की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 136 लंबित मामलों में से 57 में कार्रवाई हो चुकी है। 30 मामले हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं जबकि 9 मामलों में पुनर्विचार याचिका दायर है। मुख्यमंत्री ने एक चौंकाने वाली बात भी कही कि कुछ मामलों में खुद शिकायतकर्ताओं ने मुआवजा लेने से मना कर दिया है। बाकी बचे हुए मामलों में अलग-अलग सरकारी विभागों में फाइलें प्रक्रिया के अंतिम चरण में हैं।

मुआवजे के लिए भी तारीख पर तारीख

मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों के लिए 3 .4 करोड़ की मुआवजा राशि मंजूर की गई थी, लेकिन यह रकम उन तक समय पर नहीं पहुँची। मामला जब बॉम्बे हाईकोर्ट पहुँचा, तो अदालत ने सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट की इस 'लगाम' के बाद ही सरकार ने मुआवजे की रकम जमा करवाई।

मुंबई आस-पास
पत्रकारिता पावर नहीं रिस्पांसिबिलिटी है
DBD दो बजे दोपहर

न्यूज़ ब्रीफ

सरकारी योजनाओं में सुस्ती पर बरसे जिलाधिकारी

ठाणे। जिले के विकास और सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुँचाने के लिए जिला स्तरीय समीक्षा समिति (DLRC) की एक महत्वपूर्ण बैठक जिलाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में बैंकों के प्रदर्शन, विशेष रूप से निजी बैंकों की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाया गया। जिलाधिकारी ने वार्षिक ऋण योजना के तहत बैंकों द्वारा अब तक किए गए कार्यों की बारीकी से निरीक्षण किया। इसमें स्वयं सहायता समूहों (SHG), 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' और 'मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल थे। लक्ष्य यह है कि जिले के उद्यमियों और छोटे व्यापारियों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सके। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई कि सरकारी योजनाओं को लागू करने और जरूरतमंदों को कर्ज देने में निजी क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा। उन्होंने चेतावनी दी कि बैंकों को केवल मुनाफे पर नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व पर भी ध्यान देना होगा। वित्तीय समावेशन के तहत 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना', 'सुरक्षा बीमा योजना' और 'अटल पेंशन योजना' की प्रगति पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी का स्पष्ट निर्देश है कि जिले का हर पात्र नागरिक इन सुरक्षा कवचों के दायरे में आना चाहिए।

मेधा पाटकर फिर बनीं श्रमिक जनता संघ की अध्यक्ष

ठाणे। मजदूरों और श्रमिकों के अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई के साथ-साथ सड़कों पर संघर्ष करने वाला श्रमिक जनता संघ अपने 60 वर्ष पूरे कर चुका है। स्वतंत्रता सेनानी वसंतराव खानोलकर द्वारा वर्ष 1966 में स्थापित इस यूनियन का डायमंड जुबली वार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन ठाणे में आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को पुनः निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया और सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश खैरालिया को महासचिव नियुक्त किया गया। इस अवसर पर वर्ष 1975 से मजदूरों के अधिकारों के लिए कार्य कर रहे वरिष्ठ श्रम कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता रवींद्र नायर को विशेष रूप से सम्मानित किया गया।

सभी आईवीएफ और सोनोग्राफी सेंटर्स की जांच

मेयर ने दिए निर्देश, अवैध आईवीएफ सेंटर पर छापा

डीबीडी संवाददाता | ठाणे

बदलापुर में महिलाओं के अंडाणु के अवैध कारोबार का पर्दाफाश होने के बाद ठाणे जिले का स्वास्थ्य प्रशासन अब पूरी तरह से 'एक्शन मोड' में आ गया है। ठाणे के एक नामी अस्पताल में बिना लाइसेंस चल रहे IVF सेंटर पर हुई छापेमारी और मशीनों को सील किए जाने की कार्रवाई ने इस गिरोह के तार ठाणे शहर से भी जोड़ दिए हैं। बदलापुर में मामला सामने आने के बाद ठाणे मनपा के स्वास्थ्य विभाग को एक प्रसिद्ध अस्पताल में बिना मंजूरी के IVF सेंटर चलने की गुप्त सूचना मिली थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रसाद पाटिल के नेतृत्व में टीम ने छापा मारकर न केवल सेंटर की अनुमति रद्द की, बल्कि वहां मौजूद तीन सोनोग्राफी मशीनों को भी तुरंत सील कर दिया।

मजबूरी का फायदा और 'हार्मोनल' टॉर्चर

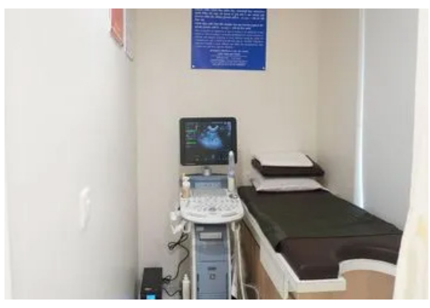

जांच में जो खुलासा हुआ वह रूह कंपा देने वाला है। गरीब महिलाओं को पैसों का लालच देकर उन्हें भारी मात्रा में इंजेक्शन दिए जाते थे ताकि उनके शरीर में सामान्य से अधिक अंडाणु (Eggs) पैदा हों। इस प्रक्रिया से महिलाओं की सेहत को गंभीर खतरा होता है, लेकिन गिरोह लाखों रुपये कमाने के लिए उन्हें इस 'जैविक दबाव' में रखता था।

लाखों की वसूली और फर्जीवाड़ा

यह गिरोह संतान की इच्छा रखने वाले अमीर दंपतियों को निशाना बनाता था और उनसे मनमानी रकम वसूलता था। चूंकि ठाणे के इस सेंटर के पास IVF प्रक्रिया के लिए कोई वैध लाइसेंस नहीं था, इसलिए यह पूरा काम चोरी-छिपे और नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा था। मेयर शर्मिला पिंपलोलकर ने इस मुद्दे पर मंगलवार को शिवसेना ग्रुप लीडर पवन कदम और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ आपात बैठक की। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि ठाणे मनपा क्षेत्र के सभी IVF और सोनोग्राफी सेंटर्स की तत्काल जांच की जाए।

40 साल की सेवा के बाद मोटरमैन को अनोखी विदाई

अंबरनाथ से सीएसएमटी तक निकली खास विदाई यात्रा

डीबीडी संवाददाता | उल्हासनगर

भारतीय रेलवे में चार दशक से अधिक समय तक सेवा देने वाले सीनियर मोटरमैन रामदास जगन्नाथ नरखेड़े को रिटायरमेंट पर अनोखे अंदाज में विदाई दी गई। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) और कल्याण में आयोजित समारोह में रेलवे अधिकारियों, कर्मचारियों और साथियों ने उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर अंबरनाथ से सीएसएमटी तक एक विशेष 'विदाई यात्रा' का आयोजन किया गया।

फूलों से सजी लोकल ट्रेन में हुआ सम्मान

इस खास विदाई यात्रा के लिए लोकल ट्रेन को फूलों और ग्रीटिंग बोर्ड से सजाया गया था। नरखेड़े अपने साथियों के साथ इस ट्रेन में अंबरनाथ से CSMT तक पहुंचे। यह यात्रा उनके 40 वर्षों की ईमानदार सेवा का सम्मान देने के लिए आयोजित की गई थी। यात्रा के दौरान रास्ते में आने वाले कई रेलवे स्टेशनों पर नागरिकों, यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। कई जगहों पर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उनका स्वागत किया गया। यह सम्मान देखकर रामदास नरखेड़े भावुक हो गए।

किसान परिवार से शुरू हुआ संघर्ष भरा सफर

रामदास नरखेड़े का जन्म विदर्भ के बुलढाणा जिले के मोटाला तालुका के छोटे से गांव अडविहिर में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद उन्होंने संघर्ष करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की। उनकी मां द्वारकाबाई और पिता जगन्नाथ नरखेड़े दूसरों के खेतों में मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे। नरखेड़े ने 2 दिसंबर 1985 को माटुंगा वर्कशॉप में रेलवे सेवा की शुरुआत की। अपनी मेहनत और लगन के बल पर उन्हें 3 दिसंबर 1994 में असिस्टेंट ड्राइवर के पद पर पदोन्नति मिली। बाद में वे सीनियर मोटरमैन बने और कई वर्षों तक हजारों यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का अनुभव दिया। रिटायरमेंट के मौके पर अपने सफर को याद करते हुए रामदास नरखेड़े ने कहा, "रेलवे ने मुझे जिंदगी दी। इस नौकरी ने मेरे परिवार को रिश्ता दी और मेरे माता-पिता की चिंता दूर की।" उनके साथियों ने उनकी लंबी और समर्पित सेवा के सम्मान में उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया।

ठाणे मनपा का मार्च की 'महा'वसूली

16 दिनों में वसूले 14.88 करोड़ रुपये

डीबीडी संवाददाता | ठाणे

ठाणे नगर निगम ने पानी के बिलों की बकाया वसूली के लिए अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निगम द्वारा दी गई ब्याज और पेनल्टी में 100% छूट की योजना का असर भी दिखने लगा है, जिसके चलते मार्च के शुरुआती 16 दिनों में ही करीब 15 करोड़ रुपये का राजस्व जमा हुआ है। ठाणे मनपा के जल आपूर्ति विभाग ने 1 मार्च से 16 मार्च 2026 के बीच 14 करोड़ 88 लाख 2 हजार 133 रुपये का बकाया वसूला है। यह सफलता मनपा द्वारा दी गई विशेष रियायत के कारण मिली है, जिसमें बकाया बिल पर लगने वाले ब्याज और पेनल्टी को पूरी तरह माफ कर दिया गया है।

अब तक की 'एक्शन रिपोर्ट'

कुल कनेक्शन काटे गए: 533
कुल नोटिस जारी: 717
पंप जब्त: 28
पंप रूम सील: 14

दिवा और कलवा में सबसे ज्यादा 'एक्शन'

निगम की टीमें मैदान में उतर चुकी हैं। सबसे ज्यादा कार्रवाई दिवा (202 कनेक्शन कट) और कलवा (155 कनेक्शन कट) में हुई है। दिवा में तो 28 पंप भी जब्त किए गए हैं और 14 पंप रूम को सील कर दिया गया है।

31 मार्च की 'डेडलाइन'

नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि यह 100% छूट केवल 31 मार्च 2026 तक ही उपलब्ध है। 1 अप्रैल से नियम बदल जाएंगे और बकायेदारों के खिलाफ और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। महापौर शर्मिला पिंपलोलकर और मनपा आयुक्त सौरभ राव ने लोगों से इस सुनहरे मौके का फायदा उठाने की अपील की है।

शहर भर में नोटिस की बरसात

केवल कनेक्शन काटना ही नहीं, बल्कि मनपा ने कानूनी चेतावनी भी दी है। 717 लोगों को नोटिस थमाए गए हैं। लोकमान्य सावरकरनगर प्रभाग समिति ने अकेले 438 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। नौपाड़ा-कोपरी, उथलसर और वर्तकनगर जैसे इलाकों में भी धड़ाधड़ कनेक्शन काटने की कार्रवाई जारी है।

करंट लगने से 7 वर्षीय बच्चे की मौत

खेलते समय हुआ दर्दनाक हादसा

डीबीडी संवाददाता | डोंबिवली

डोंबिवली पूर्व के गोग्रासवाड़ी स्थित जिजाईनगर इलाके में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 7 वर्षीय बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल फैल गया।

पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया

इस मामले में टिलकनगर पुलिस ने पिता के बयान के आधार पर आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस को दिए बयान में पिता ने किसी पर भी संदेह नहीं जताया है और कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है।

बिजली उपकरणों की सुरक्षा पर उठे सवाल

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इलाके में खुले बिजली उपकरणों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। नागरिकों ने मांग की है कि ऐसे बिजली फीडर पिलरों को सुरक्षित किया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की दुखद घटनाएं दोबारा न हों।

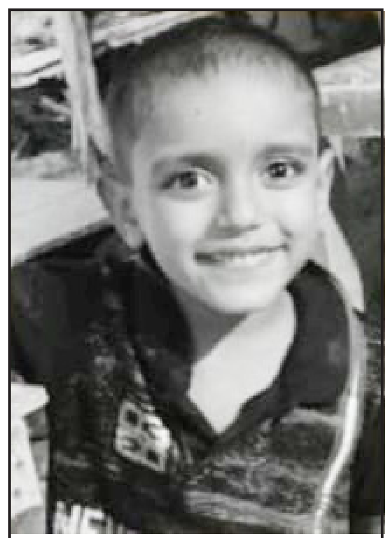

टेम्पो चालक है बच्चे का पिता

कृष्णा के पिता संजय यादव डोंबिवली क्षेत्र में 407 टेम्पो चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। परिवार पिछले आठ वर्षों से विठ्ठल कृपा बिल्डिंग में रह रहा है। परिवार में माता निशा, दादी राजपती, दादा मेवालाल यादव और बड़ा भाई अर्जुन शामिल हैं।

बिजली के फीडर पिलर को छूते ही लगा करंट

मृतक की पहचान कृष्णा संजय यादव (7 वर्ष 9 माह) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार रविवार को स्कूल की छुट्टी होने के कारण कृष्णा घर के पीछे स्थित खुले मैदान में खेल रहा था। इसी दौरान खेलते-खेलते उसकी गेंद सड़क किनारे लगे बिजली के फीडर पिलर (लाल बॉक्स) के पास चली गई। गेंद उठाने के लिए जैसे ही उसने पिलर को छुआ, उसे जोरदार करंट लग गया।

अस्पताल ले जाते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

करंट लगने के बाद कृष्णा वहीं चिपककर बेहोश हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे उठाकर स्टार कॉलोनी स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सुबह करीब 8:45 बजे उसे मृत घोषित कर दिया।

तुर्भे में सीबीजी और 'वेस्ट टू एनर्जी' प्रोजेक्ट का विरोध तेज

डीबीडी संवाददाता | नवी मुंबई

नवी मुंबई महानगरपालिका द्वारा तुर्भे के स्टोअर डम्पिंग ग्राउंड पर प्रस्तावित सीबीजी (कंप्रेस्ड बायोगैस) और 'वेस्ट टू एनर्जी' प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध तेज हो गया है। नागरिकों का आरोप है कि इस प्रोजेक्ट को जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों को विश्वास में लिए बिना आगे बढ़ाया जा रहा है। तुर्भे क्षेत्र के शिवसेना नगरसेवक सुरेश शिवाजी कुलकर्णी ने मनपा आयुक्त को पत्र लिखकर इस परियोजना का विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने मांग की है कि प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के सामने सार्वजनिक की जाए।

एसआरए पुनर्विकास पर पड़ सकता है असर

इस बीच महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से नवी मुंबई में स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (एसआरए) के तहत झोपड़पट्टी पुनर्विकास की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सर्वेक्षण कार्य जारी है। हालांकि, प्रस्तावित प्रोजेक्ट के कारण इस पुनर्विकास योजना पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

बफर जोन और प्रदूषण को लेकर चिंता

स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 500 मीटर का बफर जोन आवश्यक होता है, जहां आवासीय निर्माण पर कई प्रतिबंध लग सकते हैं। साथ ही प्रोजेक्ट से निकलने वाला धुआं और राख नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। नागरिकों ने मांग की है कि प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय प्रभाव और तकनीकी जानकारी तुरंत सार्वजनिक की जाए। अन्यथा तुर्भे के लोग एकजुट होकर बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

महंगाई भत्ते को लेकर कर्मचारियों का आंदोलन

लिखित आश्वासन के बावजूद भत्ता लागू न होने से नाराजगी

डीबीडी संवाददाता | उल्हासनगर

उल्हासनगर कृषि उत्पन्न बाजार समिति के कर्मचारियों में महंगाई भत्ते को लेकर भारी नाराजगी देखी जा रही है। कर्मचारियों का आरोप है कि छठे वेतनमान के तहत महंगाई भत्ता बढ़ाने का लिखित आश्वासन दिए जाने के बावजूद अब तक इसे पूरा तरह लागू नहीं किया गया है। इसी के विरोध में 14 कर्मचारियों ने सोमवार 16 मार्च 2026 से मुख्यालय के सामने काम बंद आंदोलन और भूख हड़ताल शुरू कर दी है।

पहले भी कर चुके हैं भूख हड़ताल

कर्मचारियों के अनुसार छठा वेतनमान मंजूर होने के बाद भी उन्हें उसका पूरा लाभ नहीं मिला। इससे पहले 21 अगस्त 2025 को भी कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की थी, जिसमें मांग की गई थी कि समिति के कर्मचारियों को छठे वेतनमान के अनुसार सभी लाभ दिए जाएं।

समिति ने दिया था लिखित भरोसा

उस समय बाजार समिति के चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी की मध्यस्थता से 22 अगस्त 2025 को कर्मचारियों को लिखित आश्वासन दिया गया था। इस पत्र के अनुसार अगस्त 2025 के वेतन में 20 प्रतिशत महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की गई थी, जबकि नवंबर 2025 में अतिरिक्त 20 प्रतिशत बढ़ोतरी का वादा किया गया था।

प्रशासन ने दी थी अलग शर्त

इस शिकायत के जवाब में बाजार समिति ने 19 जनवरी 2026 को कहा था कि रिकवरी में बढ़ोतरी होने के बाद वेतन और प्रमोशन पर विचार किया जाएगा। हालांकि कर्मचारियों का कहना है कि लिखित समझौते में ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई थी। इसी मुद्दे को लेकर दत्ता भोईर, नंदू भोइते, आकाश राउत, विनोद पाटिल, मोरेश्वर डाबरे, संतोष वैले, प्रभाकर विशे, कमलाकर शेलार समेत कुल 14 कर्मचारियों ने काम बंद आंदोलन शुरू किया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि आंदोलन के दौरान बाजार समिति के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अनाज और दालों की आवक का रिकॉर्ड नहीं होने से यदि आर्थिक नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी समिति प्रशासन की होगी।

दूसरा चरण अब तक नहीं हुआ लागू

कर्मचारियों का आरोप है कि नवंबर 2025 से लागू होने वाली महंगाई भत्ते की दूसरी बढ़ोतरी आज तक नहीं दी गई है। इस मामले में कर्मचारियों ने 26 दिसंबर 2025 को जिला उप निबंधक कार्यालय में लिखित शिकायत भी की थी।

समुद्र में बढ़ेगी भारत की चौकसी

तटरक्षक बल के दो नए पोतों का निर्माण शुरू

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 'अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोतों' के निर्माण में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। मंगलवार, 17 मार्च 2026 को इस परियोजना के दूसरे और तीसरे जहाज की 'कील लेईंग' रस्म पूरी की गई, जो जहाज के ढांचे के निर्माण की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है। जहाज निर्माण में 'कील लेईंग' का बड़ी महत्व है जो किसी इमारत के लिए नींव रखने का होता है। रत्नागिरी में आईजी सुधीर साहनी और एमडीएल के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में Y-16402 और Y-16403 (दूसरे और तीसरे पोत) के हल (Hull) संयोजन की औपचारिक शुरुआत हुई। यह एमडीएल के लिए 'नवरत्न' डीपीएसयू के रूप में एक बड़ी उपलब्धि है।

स्वदेशी निर्माण और भारी निवेश

इस पूरी परियोजना की लागत 1614.89 करोड़ है, जिसके तहत कुल 6 पोत बनाए जाने हैं। यह 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक बड़ा कदम है, जहाँ भारतीय शिपयार्ड स्वदेशी डिजाइन और तकनीक का उपयोग करके अंतरराष्ट्रीय मानकों (ABS और IRS) के पोत तैयार कर रहा है। निर्धारित समय सीमा के अनुसार, दूसरे पोत की सुपुर्दगी दिसंबर 2027 में और तीसरे पोत की मई 2028 में होनी है। आज की कील लेईंग से यह साफ हो गया है कि परियोजना अपने तय शेड्यूल पर चल रही है, जिससे भारतीय तटरक्षक बल की परिचालन क्षमता में भारी इजाफा होगा।

समुद्री सीमा की सुरक्षा का 'कवच'

इन जहाजों का मुख्य काम भारत के समुद्री क्षेत्र में गश्त और निगरानी करना होगा। ये पोत केवल गश्त ही नहीं करेंगे, बल्कि मत्स्य संरक्षण, तस्करी रोकना, समुद्री डकैती के खिलाफ कार्रवाई और समुद्र में फंसे लोगों की खोज व बचाव जैसे कठिन मिशनों को भी अंजाम देंगे।

रफ्तार और ताकत का बेजोड़ संगम

इन अगली पीढ़ी के पोतों (NGOPV) को 9000 किलोवाट के शक्तिशाली इंजन और दोहरे प्रोपेलर से लैस किया जाएगा। इनकी संविदात्मक गति 23 समुद्री नॉट से अधिक होगी, जो समुद्र में पीछा करने और त्वरित कार्रवाई के लिए बेहद जरूरी है। इन्हें उच्च गति वाले जलयान के रूप में डिजाइन किया गया है।

अवैध पार्किंग से 'विनायक कट्टा' पर बुजुर्ग असुरक्षित

सीनियर सिटिजन के लिए बना स्थान पार्किंग में तब्दील

डीबीडी संवाददाता | ठाणे

ठाणे ईस्ट के अष्टविनायक चौक स्थित 'सीनियर सिटिजन विनायक कट्टा', जिसे मिनी शिवाजी पार्क के नाम से भी जाना जाता है, इन दिनों अवैध और बेतरतीब वाहन पार्किंग की वजह से समस्या का सामना कर रहा है। समाजसेवी और वरिष्ठ पत्रकार डॉ. प्रशांत का कहना है कि बुजुर्गों के बैठने और आपसी संवाद के लिए बनाए गए इस स्थान का मूल उद्देश्य ही अव्यवस्थित पार्किंग के कारण प्रभावित हो रहा है।

नगरपालिका ने विशेष रूप से कराया था निर्माण

ठाणे महानगरपालिका ने इस कट्टा का निर्माण सीनियर सिटिजन के लिए विशेष रूप से किया था। यह स्थान सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। कुछ महीने पहले शेड खराब होने के बाद राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कोष से इसका नवीनीकरण किया गया और यहां मजबूत ग्रेनाइट की बेंच लगाकर सुंदर विनायक कट्टा तैयार किया गया।

नवीनीकरण के बाद भी नहीं रुकी अवैध पार्किंग

स्थानीय लोगों का कहना है कि कट्टा के सामने फेंस के पास दोपहिया और चारपहिया वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग लगातार बनी हुई है। कई बार बाहर से आने वाले वाहन चालक भी यहां मनमाने तरीके से गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिससे बुजुर्गों के लिए यहां बैठना और आना-जाना मुश्किल हो जाता है।

बुजुर्गों के लिए खतरा, जगह रहने लगी सुनसान

अतिक्रमण जैसी पार्किंग के कारण कट्टा के पास बैठने वाले बुजुर्गों को दुर्घटना का डर बना रहता है। यही वजह है कि यह सुंदर और उपयोगी स्थान अब अक्सर खाली दिखाई देता है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए यहां वाहनों की पार्किंग पूरी तरह बंद होनी चाहिए।

'नो पार्किंग' घोषित करने की मांग

स्थानीय नागरिकों ने ठाणे महानगरपालिका और ट्रैफिक विभाग से मांग की है कि अष्टविनायक चौक के इस हिस्से को 'नो पार्किंग' जोन घोषित किया जाए और अवैध पार्किंग के खिलाफ नियमित कार्रवाई की जाए। वहीं समाजसेवी पांडुरंग दलवी ने भी पुलिस प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

राज्य में 80 पुराने अधिनियम और कानून रद्द

विधानसभा में बिल पारित

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र में अनुपयोगी हो चुके 80 पुराने कानूनों और अधिनियमों को रद्द करने वाला विधेयक मंगलवार को राज्य विधानसभा में पारित कर दिया गया। इन कालबाह्य नियमों के कारण प्रशासनिक कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो रही थीं, इसलिए राज्य सरकार ने इन्हें समाप्त करने का निर्णय लिया। यह विधेयक सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री आशीष शेलार द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। चर्चा के बाद सदन ने इसे मंजूरी दे दी। सरकार के अनुसार इनमें से कई अधिनियम स्वतंत्रता से पहले लागू किए गए थे और वर्तमान समय में उनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है।

सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए मंत्री शेलार ने कहा कि संवैधानिक बदलाव, राज्य पुनर्गठन और नए कानून लागू होने के कारण कई पुराने अधिनियम अप्रासंगिक हो गए हैं। इन अधिनियमों का रिकॉर्ड में बने रहना प्रशासन में भ्रम और अनावश्यक जटिलता पैदा कर रहा था।

राज्य के सभी कानूनों की हो रही समीक्षा

राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में लागू सभी अधिनियमों की समीक्षा प्रक्रिया शुरू की है। इसी क्रम में बॉम्बे एक्ट, बॉम्बे रेगुलेशन्स, बंगाल रेगुलेशन्स, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड वर्धा एक्ट, हैदराबाद एक्ट और मध्य प्रदेश एक्ट जैसे पुराने कानूनों को रद्द करने का निर्णय लिया गया है।

इन श्रेणियों के अधिनियम किए गए समाप्त

सरकार द्वारा समाप्त किए गए 80 अधिनियमों में 24 बॉम्बे एक्ट्स, 8 सेंट्रल प्रोविंसेस वर्धा एक्ट्स, 18 हैदराबाद एक्ट्स और 3 मध्य प्रदेश एप्रोप्रिएशन एक्ट्स शामिल हैं। इसके अलावा बंगाल एल्यूवियम एंड सेडिमेंट रेगुलेशन 1825, लोन इंटरेस्ट मॉर्गेज एक्सेप्टेंस रेगुलेशन 1827, भड़ौच एवं खेड़ा एन्कम्बर्ड लैंड एक्ट 1877, मुंबई एक्साइज एक्ट 1878, बोस्टल स्कूल एक्ट 1929, महाराष्ट्र ओपियम स्मगलिंग एक्ट, मुंबई ग्रेन कंट्रोल एक्ट 1939 और मुंबई कॉटन कंट्रोल एक्ट 1942 जैसे कई पुराने कानून भी समाप्त किए गए हैं।

आरटीई प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी अनएडेड स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण के लिए प्रवेश प्रक्रिया में अहम बदलाव किए गए हैं। अब ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मार्च 2026 कर दी गई है, जिससे अधिक अभिभावकों को आवेदन का अवसर मिल सके। बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर बेंच के निर्देशों के अनुसार, स्कूल से दूरी की 1 किलोमीटर की शर्त में ढील दी गई है। अब अभिभावक 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों का चयन कर सकते हैं, जिससे बच्चों को अधिक विकल्प मिलेंगे। 16 मार्च 2026 तक आवेदन करने वाले अभिभावकों को अपने आवेदन में सुधार करने की सुविधा भी दी गई है। इसके लिए पोर्टल पर 'अनकन्फर्म' और 'फिर से कन्फर्म' करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है, जिसकी जानकारी पॉप-अप विंडो के माध्यम से दी जा रही है। बालासाहेब रक्षे, शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक), जिला परिषद ठाणे ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार पात्र बच्चों को अधिक अवसर देने के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ाई गई है। दूरी की शर्त में ढील से अभिभावकों को अपने पसंदीदा स्कूल चुनने के ज्यादा विकल्प मिलेंगे।

खार पुलिस स्टेशन का अधिकारी 15 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

आर्थिक राजधानी मुंबई में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में मुंबई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने खार पुलिस स्टेशन में तैनात एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को 15 लाख ' की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अधिकारी ने अदालत में चल रहे जमीन विवाद को शिकायतकर्ता के पक्ष में सुलझाने और कानूनी प्रक्रिया में ढील देने के बदले यह रकम मांगी थी।

जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता का एक कीमती जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जो फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। आरोप है कि खार पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने इस मामले को शिकायतकर्ता के पक्ष में सुलझाने का भरोसा देकर बड़ी रकम की मांग की थी। शुरुआती बातचीत में लाखों ' की डील तय हुई और पहली किस्त के रूप में 15 लाख ' देने की बात सामने आई।

शिकायतकर्ता ने ACB से की शिकायत

शिकायतकर्ता इस भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत मुंबई ACB से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी दी। शिकायत मिलने के बाद ACB ने मामले का सत्यापन किया और रिश्वत की मांग की पुष्टि होने पर कार्रवाई की योजना बनाई। तय योजना के अनुसार जैसे ही शिकायतकर्ता ने रिश्वत की रकम पुलिस अधिकारी को सौंपी, वहां सादे कपड़ों में मौजूद ACB अधिकारियों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आरोपी के पास से 15 लाख ' की पूरी रकम बरामद कर ली गई है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज

गिरफ्तारी के बाद आरोपी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। ACB अब यह भी जांच कर रही है कि इस मामले में पुलिस स्टेशन के अन्य कर्मचारी या कोई वरिष्ठ अधिकारी शामिल तो नहीं हैं। ACB की टीम आरोपी अधिकारी की संपत्ति और पुराने मामलों के रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। इस कार्रवाई को मुंबई पुलिस में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा संदेश माना जा रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन पहले भी भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति की बात करता रहा है।

युवाओं के लिए 'रोजगार की गारंटी'

आईटीआई का होगा कायाकल्प, दावोस निवेश से खुलेंगे 40 लाख नौकरियों के द्वार

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र के कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने मंगलवार को विधान परिषद में राज्य के युवाओं के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है। एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक से मिली भारी आर्थिक मदद के जरिए महाराष्ट्र अब युवाओं को न सिर्फ देश में, बल्कि विदेशों में भी रोजगार दिलाने के लिए तैयार है। राज्य की आईटीआई (ITI) संस्थाओं को अब आधुनिक बनाया जाएगा। इसके लिए एशियाई विकास बैंक (ADB) ने 4200 करोड़ और विश्व बैंक ने 1400 करोड़ की भारी-भरकम राशि मंजूर की है। इस फंड से न सिर्फ इमारतों का पुनर्निर्माण होगा, बल्कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को भी इतना सक्षम बनाया जाएगा कि युवाओं को नौकरी ढूंढने में भटकना न पड़े। मुख्यमंत्री

युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लाभार्थियों के लिए सरकार ने छह सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया है। इसमें आईटीआई के अल्पकालीन पाठ्यक्रमों में 10% आरक्षण, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 10% प्राथमिकता, उद्योग विभाग को प्रशिक्षित युवाओं की सूची नियमित रूप से उपलब्ध कराना, महास्वयं पोर्टल पर 'मैच मेकिंग पोर्टल' की सुविधा, रोजगार मेलों में विशेष व्यवस्था और निजी कंपनियों की जरूरत के अनुसार विशेष प्रशिक्षण शामिल हैं।

मुख्यमंत्री महाफंड योजना अप्रैल से शुरू

यह एक क्रांतिकारी योजना है जिसमें 30 लाख युवा ऑनलाइन परीक्षा देंगे। चुने गए 1 लाख युवाओं को 5 लाख तक का कर्ज मिलेगा, जिसका आधा ब्याज सरकार भरेगी। सफल स्टार्टअप्स को सरकार 25 लाख तक की तकनीकी मदद भी देगी ताकि वे अपना बिजनेस बड़ा कर सकें। दावोस में हुए 30 लाख करोड़ के निवेश समझौतों का सबसे बड़ा फायदा महाराष्ट्र के कुशल युवाओं को मिलने वाला है। सरकार का अनुमान है कि इन प्रोजेक्ट्स से आने वाले समय में 40 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अब महाराष्ट्र का युवा जर्मनी, फ्रांस और अन्य देशों में भी नौकरी कर सकेगा। इसके लिए स्वामी विवेकानंद प्रबोधिनी केंद्र सहित 6 स्थानों पर विदेशी भाषाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी।

SERENITY REALTY SOLUTIONS (MUMBAI)

Experienced Consultancy Firm offering Professional Commission-based Services for Developers, Landowners, Investors & Corporate Houses.

- Land Acquisition & Joint Venture Facilitation.
- Real Estate Project Opportunities.
- Government Liaisoning & Approvals.
- Business Collaborations Across Industries.
- Financial & Strategic Facilitation.

For Further Details Contact : 9870061155

मध्य रेल

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा धारा 84 BNSS

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अभियुक्त **सैयद जेनल अब्दीन** पुत्र मो. शेर अली निवासी रुम नं. 14, चाल नं. 04, झकिना बाई चाल, काजू पाडा पाइप लाइन, जामा मस्जिद, ज्वाला कुर्ला, (वेस्ट), मंबई, महाराष्ट्र ने मुकदमा अं. सं. 01/25 धारा 3RP(UP) Act के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल, शकूरबस्ती, दिल्ली के अधीन दंडनीय अपराध किया है (यह संदेह है कि उसने किया है)। उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **सैयद जेनल अब्दीन** यहाँ नहीं रहता और मुझे समुचित रूप से दर्शित कर दिया गया है कि **सैयद जेनल अब्दीन** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामिल से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)।

अतः इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि उक्त **सैयद जेनल अब्दीन** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **27.04.2026** को या इससे पहले उपस्थित हो।

आदेशानुसारः श्री वैभव गर्ग
प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

DE-997

कुळगांव बदलापूर नगरपरिषद

नवीन प्रशासकीय ईमारत, म. गांधी चौक रोड, बदलापूर रेल्वे स्टेशन (पूर्व).
कुळगांव, पिन - ४२१५०३, ता. अंबरनाथ जि. ठाणे.

ई-मेल : - coud.kulgaonbadalapur@maharashtra.gov.in. वेबसाइट :- kbmc.gov.in.

जा.क्र./साबां/ २९९७ /२०२५-२६ दिनांक १७/०३/२०२६

जाहीर ई-निविदा शुध्दीपत्रक सुचना क्र. ९५/२०२५-२६

कुळगांव बदलापूर नगरपरिषदेने पेपरामध्ये जाहीर ई-निविदा सुचना क्र.९५/२०२५-२६ जा.क्र.कुबनप/साबां/२९८३/२०२५-२६ दि.१३/०३/२०२३ रोजीची नगरपरिषद विविध ठिकाणी विकासित कामांची एकूण ५ कामाची महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर (http://mahatenders.gov.in) जाहीर ई-निविदा प्रसिध्द करण्यात आली होती. **परंतु काही तांत्रिक अडचणीमुळे प्रसिध्द करण्यात आलेली जाहीर ई-निविदा सुचना रद्द करण्यात येत आहे. याची नोंद घ्यावी.**

सही/-
मुख्याधिकारी
कुळगांव बदलापूर नगरपरिषद
कुळगांव

महाराष्ट्र शासन

इलाखा शहर विभाग, (सार्वजनिक बांधकाम विभाग - PWD)

ई-निविदा सूचना क्रमांकः 105, वर्ष 2025-2026

मुंबई के इलाखा शहर विभाग के कार्यकारी अभियंता (फोन नंबरः 22016975 / 22016977) द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के सार्वजनिक बांधकाम विभाग में पंजीकृत योग्य श्रेणी के ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य के लिए B-1 प्रारूप में ई-निविदा (ऑनलाइन) आमंत्रित की जाती है।
निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, मुंबई के पास सुरक्षित है।

अ.क्र.	कामाचे नाव	रक्कम
१	विधान भवन मुंबई येथील २० वा मजला व ९ व्या मजल्यावरील टेरेसला जल प्रतिबंधक उपाययोजना व पाईप लाईन दुरुस्ती करणे बाबत	९८.५१
२	विधान भवन मुंबई येथील २ ऱ्या मजल्यावरील (पूर्व बाजू) टेरेसला जल प्रतिबंधक उपाययोजना व पाईप लाईन दुरुस्ती करणे	९८.५२
३	विधान भवन मुंबई येथील २ ऱ्या मजल्यावरील (पश्चिम बाजू) टेरेसला जल प्रतिबंधक उपाययोजना व पाईप लाईन दुरुस्ती करणे	९८.७७
४	विधान भवन मुंबई येथील २ ऱ्या मजल्यावरील (दक्षिण व उत्तर बाजू) टेरेसला जल प्रतिबंधक उपाययोजना व पाईप लाईन दुरुस्ती करणे	९७.९२
५	विधान भवन येथील तळघरातील सी. आय व जी. आय पाईप लाईनचे नुतनीकरण करणे व पॉलिमर प्लास्टर, आवश्यकती फीटींग्स करणे	४६.४९
६	विधान भवन येथील गोल इमारतीतील सी.आय व जी.आय पाईप लाईनचे नुतनीकरण करणे व पॉलिमर प्लास्टर, आवश्यकती फीटींग्स करणे	९८.९३
७	विधान भवन येथील उंच इमारतीतील पश्चिम बाजू कडील महीला प्रसाधनगृह डक्ट मधील सी.आय व जी.आय पाईप लाईनचे नुतनीकरण करणे व पॉलिमर प्लास्टर, आवश्यकती फीटींग्स करणे	६९.२९
८	विधान भवन येथील उंच इमारतीतील पूर्व बाजू कडील पुरुष प्रसाधनगृह डक्ट मधील सी.आय व जी.आय पाईप लाईनचे नुतनीकरण करणे व पॉलिमर प्लास्टर, आवश्यकती फीटींग्स करणे	६५.७३
९	विधान भवन मुंबई येथील उंच इमारतीच्या मागील बाजूस असलेल्या महानगर पालिकेची पाण्याच्या पाईप लाईनचे नुतनीकरण करणे	२०.६५
१०	विधान भवन येथील उंच इमारतीतील ९ व्या मजल्यावरील दालन क्र. ९०१ चे नुतनीकरण करणे.	९९.१८
११	विधान भवन येथील उंच इमारतीतील १० व्या मजल्यावरील दालन क्र. १००२ चे नुतनीकरण करणे.	९०.७९
१२	विधान भवन मुंबई येथील तिसऱ्या मजल्यावरील मा. मंत्री महोदयांच्या दालनात दुरुस्ती व नुतनीकरण करणे.	१९.७८
१३	विधान भवन मुंबई येथील गोल इमारत चौथ्या मजल्यावरील मा. मंत्री महोदयांच्या दालनात दुरुस्ती व नुतनीकरण करणे.	२६.९९
१४	तेलंग मेमोरियल गर्ल्स हॉस्टेल, 'सी' रोड, रोड, चर्चगेट, मुंबई येथे पहिल्या मजल्यापासून पाचव्या मजल्यापर्यंत बाथरूम आणि शौचालयांचे नूतनीकरण करणे.	७७.४१
१५	मलबार हिल, मुंबई येथे पहिल्या मजल्यावरील तळमजल्यावरील पहिल्या पिठाच्या शौचालय ब्लॉकचे नूतनीकरण, रंगकाम, प्लास्टरिंग आणि शौचालय ब्लॉकची दुरुस्ती करणे.	१७.१४
१६	तेलंग स्मारक येथे बु बंक बेड, शू रॅक, टेबल, खुर्चा इत्यादी मुलींचे वसतिगृह, रोड, चर्चगेट, मुंबई येथे पुरवणे आणि पुरवठा करणे.	२०.३२
१७	फोर्जेट मंझिल बिल्डिंग, मुंबई येथील फ्लॅट क्रमांक ५ ची दुरुस्ती आणि नूतनीकरण करणे.	१३.१७
१८	फोर्जेट मंझिल, फ्लॅट क्रमांक १, बँड रोड, मुंबई येथे टॉयलेट बाथ फ्लोअरिंगचे नूतनीकरण, डब्ल्यू.सी. पॅन, अंतर्गत प्लास्टर आणि रंगकाम, दरवाजे आणि दरवाजे आणि खिडक्यांची दुरुस्ती, खिडकीची ग्रिल, फरशीची दुरुस्ती करणे.	१.९४
१९	चर्नी रोड, मुंबई येथील नवीन प्रेस बिल्डिंग येथील दुसऱ्या मजल्यावरील स्टेशनरी कार्यालयाच्या शौचालय, वॉटरप्रूफिंग, दादो आणि फरशी आणि संबंधित कामांची दुरुस्ती करणे.	१२.०६
२०	मुंबईतील चर्नी रोड येथील न्यू प्रेस बिल्डिंग येथील दुसऱ्या मजल्यावरील स्टेशनरी कार्यालयातील सहाय्यक संचालक केबिन, मेकॅनिकल इंजिनिअर केबिन आणि स्टाफ केबिनची दुरुस्ती करणे.	१४.५८

ई-निविदा उपलब्ध कालावधी दि. १८.३.२०२६ ते दि. २५.३.२०२६ पर्यंत.
ई-निविदा उघडणे दि. २७.३.२०२६ रोजी दुपारी ३.०० वाजता
निविदा सुचने मध्ये काही बदल/सुधारणा करावयाची असल्याचे शुध्दीपत्रक वृत्तपत्रामध्ये प्रसिध्द करण्यात येणार नाही. त्याबत सर्व बदल ऑनलाईन निविदा प्रक्रियेमध्ये प्रसिध्द केले जाईल.
खालील संकेतस्थळावरुन ई-निविदाची सर्व माहीती उपलब्ध आहे.

1) www.mahapwd.com
2) http://mahatenders.gov.in

जा.क्रं. इसराविं/निलि/२६५८
इलाखा शहर विभाग, मुंबई यांचे कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,
२रा मजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान रोड, फोर्ट,
मुंबई- ४०० ००१.
Email: presidency.ee@mahapwd.gov.in
दिनांक १६/३/२०२६

सही/-
(व्ही. ए. पाटसकर)
कार्यकारी अभियंता,
इलाखा शहर विभाग, मुंबई.

मध्य रेल
सोलापुर मंडल
परिवहन कार्य

मंडल रेल प्रबंधक (यांत्रिक), मध्य रेल, सोलापुर के द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए ख्यातिप्राप्त प्रतिष्ठानों/ठेकेदारों से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती हैं। **निविदा सूचना क्रमांकः GEM/2026/B/7340320 dated: 13.03.2026; कार्य का नाम स्थान सहितः** सोलापुर कोचिंग डिपो से माटुंगा वर्कशॉप, परेल वर्कशॉप या भारतीय रेलवे पर किसी अन्य नामित वर्कशॉप तक पहियों सहित असेंबल की गई बोगियों के परिवहन का संविदा कार्य, उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ खुले फ्लैट ट्रक में जेम के माध्यम से किया जाएगा। **निविदा कार्य पद्धतिः** दो पैकेट सिस्टम, **कार्य की औसत लागतः** रु. 2,39,81,299.25, **निविदा प्रपत्र मूल्यः** रु. Nil, **कार्यालय का पता, जहां से निविदा प्रपत्र खरीदे जा सकते हैं:** मंडल रेल प्रबंधक (यांत्रिक), मध्य रेल, सोलापुर; **जमा करने योग्य बयाना रकमः** रु. 2,69,910/-, **कार्य की समापन अवधिः** तीन साल कार्य की प्रारंभ की तिथि से, **निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि एवं समयः** 06.04.2026 को 10:00 बजे, **निविदा बक्शा खुलने की तिथि एवं समयः** 06.04.2026 को 10:30 बजे, **वेबसाइट विवरण एवं सूचना बोर्ड लोकेशन जहां से निविदा के संपूर्ण विवरण देखे जा सकते हैं: www.gem.gov.in**

वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता,
मध्य रेलवे, सोलापुर

DE/Sur-06

सुरक्षित यात्रा करें,
फुटबोर्ड पर यात्रा न करें

मध्य रेल
भुसावल मंडल
ई-निविदा सूचना संख्या म.रे.प्र. (कार्य) भुसावल / 07 / 2026

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल रेल प्रबंधक (कार्य) मध्य रेल, भुसावल द्वारा पंजीकृत निविदाकारों के लिए ई-निविदा निम्नलिखित कार्यों के लिए आमंत्रित किया जाता है-जो वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है/देखे जा सकते हैं। **ई-निविदा संख्याः** DRM W BSL 07 2026t1(संक्षिप्त नाम), **कार्य का नामः** वरिष्ठ मंडल अभियंता (पूर्व) के अधिकार क्षेत्र में BSL-BD खंड में 56.537 ट्रैक किलोमीटर का TRR (P) कार्य। **अनुमानित लागतः** 4,36,13,965.85, **बोली प्रतिभूतिः** 3,68,100/-, **Notes: (i)** निविदा अनुक्रमांक 1 की अंतिम तिथि 02.04.2026 समय 15:00 बजे तक। **(ii)** संभावित निविदाकारों से अनुरोध है वे निविदाओं और शुद्धिपत्र यदि कोई हो तो अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर देख सकते हैं। **(iii)** निविदा सूचना मं.रे.प्र.(कार्य) कार्यालय, भुसावल के नोटिस बोर्ड पर भी लगाई गई है। **(iv)** निविदाकार उपर्युक्त ई-निविदा में केवल वेबसाइट **www.ireps.gov.in** के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भाग ले सकते हैं। और ई-निविदा के लिए मैन्युअल ऑफर प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है। यदि कोई मैन्युअल ऑफर प्रस्तुत किया जाता है तो उसे न तो खोला जाएगा और न ही उस पर विचार किया जाएगा। **(v)** निविदा दस्तावेज और EMD की लागत का भुगतान IREPS पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन भुगतान प्रणाली जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड आदि से किया जा सकता है।

DE/03

सुरक्षित यात्रा करें,
फुटबोर्ड पर यात्रा न करें

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

ई-टेंडर सूचना

विभाग	:	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
सेक्शन	:	मुख्य अभियंता (SWM) / सहायक अभियंता (SWM) F/नॉर्थ
बिड नंबर	:	2026-MCGM-1287746-1
विषय	:	'एम.एल. स्टोर, RAK रोड, वडाला (F/नॉर्थ वार्ड) में प्रथम एवं द्वितीय शिफ्ट चौकी के लिए सेवा इंटरफेस का पुनर्गठन और सुधार संरचनात्मक रूप से एकीकृत ओवरहेड सुरक्षा प्रणाली की स्थापना सुरक्षा हेतु संरक्षित enclosure (घेरा) का प्रावधान'
बिड शुरू होने की तिथि व समय	:	18.03.2026, सुबह 11:00 बजे से
बिड समाप्त होने की तिथि व समय	:	24.03.2026, शाम 4:00 बजे तक
वेबसाइट	:	https://mahatenders.gov.in (महाराष्ट्र सरकार की ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट)
संपर्क व्यक्तिः-		
अ) नाम	:	श्री अमोल गीते, सहायक अभियंता (SWM), F/नॉर्थ
ब) टेलीफोन	:	022-24014356
स) ईमेल आईडी	:	aeswm01.fn@mcgm.gov.in

हस्ता./
सहायक अभियंता,(SWM) F/उत्तर

पीआरओ /3322/विज्ञा./2025-26

हल्का बुखार होने पर डॉक्टर से मिलें।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

खाताः जल अभियंता,
क्र.सहा.अभि.न.बा.वि/६७३१/ प्र.ज.वा दि. १६.०३.२०२६

ई-निविदा सुचना

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (मर्चेंट कॉर्पोरेशन) निम्नलिखित सूचीबद्ध कार्यों के लिए इच्छुक बोलीदाताओं से ऑनलाइन ई-निविदा आमंत्रित करता है। निविदाओं के वितरण और बिक्री की तिथि और समय, तथा निविदाओं की बिक्री के लिए निर्धारित तिथि और समय से संबंधित विवरण बृहन्मुंबई नगर निगम की वेबसाइट http://portal.mcgm.gov.in और महानिविदा वेबसाइट http://mahatenders.gov.in पर निविदा अवलोकन के अंतर्गत प्रकाशित/अपलोड कर दिए गए हैं।

अ.क्र.	टेंडर नं	निविदा का विषय
1	2026_MCGM_1287459_1	**सहायक अभियंता शहरी बाह्य विभाग (प्रमुख जल नहरें) के अधीन, विभिन्न कार्यशाला मशीनों की संपूर्ण मरम्मत और रखरखाव कार्य के संबंध में।**

इच्छुक बोलीदाताओं को विस्तृत जानकारी के लिए महा निविदा वेबसाइट यानी http://mahatenders.gov.in और बृहन्मुंबई महानगरपालिका की वेबसाइट यानी http://portal.mcgm.gov.in पर जाएं।

हस्ता /-
कार्यकारी अभियंता
(मुख्य निर्माण कार्य) जल निर्माण कार्य

पीआरओ/ 3306 /विज्ञा./2025-26

हल्का बुखार होने पर डॉक्टर से मिलें।

संपादकीय

वांगचुक की रिहाई

आखिरकार गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम हटाने से जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई हो गई है। वांगचुक गत वर्ष सितंबर से जोधपुर जेल में बंद थे, जिसको लेकर विपक्षी राजनीतिक दल व विभिन्न सामाजिक संगठन तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहे हैं। अब सरकार की दलील है कि यह फैसला लद्दाख में शांति, स्थिरता और संवाद का माहौल बनाने के लिये लिया गया है। वहीं विपक्षी राजनीतिक दलों का कहना है कि 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होनी थी। गिरफ्तारी का आधार मजबूत न होने पर केंद्र सरकार को उन्हें रिहा करने को बाध्य होना पड़ा है। उल्लेखनीय है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित जलवायु कार्यकर्ता, अभिनव शैक्षिक व वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए चर्चित सोनम वांगचुक को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत बीते साल सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। दरअसल, वे लंबे समय से लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और उसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने वाले आंदोलन से जुड़े रहे। उन्होंने कई बार अनशन किया। पदयात्रा के जरिये दिल्ली पहुंचकर भी उन्होंने अनशन किया था। लेकिन सितंबर में आंदोलन के हिंसक होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं केंद्र सरकार की दलील है कि क्षेत्र के लोगों की मांगों का समाधान निकालने के लिये लद्दाख के अलग-अलग समुदायों, नेताओं और संगठनों से निरंतर बातचीत के प्रयास जारी हैं। साथ ही लद्दाख के लिये सभी जरूरी सुरक्षा उपाय करने की बात कही गई है। वहीं विपक्षी दल सवाल पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तारी की तार्किकता क्या थी? क्या लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात कहने की आजादी का अतिक्रमण नहीं हो रहा है? नागरिक संगठनों से जुड़े लोगों ने वांगचुक को उनके ठंडे प्रदेश लद्दाख से 1400 किमी दूर गर्म प्रदेश राजस्थान की जोधपुर जेल में रखने पर भी सवाल उठाये थे। उल्लेखनीय है कि बीते माह शीर्ष अदालत ने भी सोनम वांगचुक की खराब सेहत के मद्देनजर, उनकी हिरासत पर पुनर्विचार करने को कहा था। दरअसल, बार-बार पेटदर्द की शिकायत पर उनकी पत्नी ने विशेषज्ञ डॉक्टरों से जांच करवाने के लिये आवेदन किया था। साथ ही कोर्ट से मासिक स्वास्थ्य रिपोर्ट की भी मांग की थी। तब शीर्ष अदालत की पीठ ने टिप्पणी की थी कि यदि हिरासत के आदेश में कानूनी त्रुटियां हैं तो इसे रद्द भी किया जा सकता है। वहीं सरकार की दलील थी कि आंदोलन को हिंसक बनाने में भूमिका के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू करने के पर्याप्त कारण मौजूद थे। वहीं विपक्षी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वांगचुक को 170 दिन हिरासत में रखने का हिसाब कौन देगा? वे इस मामले में केंद्र की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं। अन्य विपक्षी दल भी इस रिहाई के बाद केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। वे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बेजा इस्तेमाल के आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि लद्दाख के पर्यावरण व हक की मांग उठाने की कीमत वांगचुक ने चुकाई है।

शख्सियत | अरुंधति भट्टाचार्य

साहस, नेतृत्व और ईमानदारी की मिसाल

भारत के बैंकिंग इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने केवल पद नहीं संभाला, बल्कि पूरे तंत्र की दिशा बदल दी। अरुंधति भट्टाचार्य ऐसा ही एक प्रेरक नाम है। वे भारतीय स्टेट बैंक की पहली महिला अध्यक्ष बनीं और अपने नेतृत्व, निर्णय क्षमता तथा दूरदर्शिता से यह साबित कर दिया कि दृढ़ इच्छाशक्ति और मेहनत से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता।

अरुंधति भट्टाचार्य का जन्म 18 मार्च 1956 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता इंजीनियर थे और मां गृहिणी थीं। परिवार में शिक्षा और अनुशासन को विशेष महत्व दिया जाता था। बचपन से ही वे मेधावी और आत्मविश्वासी थीं। उन्होंने कोलकाता के प्रतिष्ठित प्रेसीडेंसी कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने का निर्णय लिया, जो उस समय महिलाओं के लिए अपेक्षाकृत चुनौतीपूर्ण क्षेत्र माना जाता था।

सन् 1977 में उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही युवती एक दिन देश के सबसे बड़े बैंक का नेतृत्व करेगी। लेकिन अरुंधति भट्टाचार्य ने अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी के बल पर धीरे-धीरे हर चुनौती को पार किया और लगातार ऊंचाइयों की ओर बढ़ती गईं। अपने लगभग चार दशकों के बैंकिंग करियर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। उन्होंने कॉरपोरेट बैंकिंग, विदेशी व्यापार, निवेश बैंकिंग और मानव संसाधन जैसे कई क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त किया। यही विविध अनुभव बाद में उनके नेतृत्व की सबसे बड़ी ताकत बना। वे हमेशा मानती थीं कि किसी भी संस्था को मजबूत बनाने के लिए पारदर्शिता, अनुशासन और नवाचार जरूरी हैं। सन् 2013 में अरुंधति भट्टाचार्य भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्ष बनीं। यह केवल उनके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि लगभग 200 वर्षों के इतिहास में पहली बार किसी महिला ने इस पद को संभाला था। उस समय बैंक कई चुनौतियों से जूझ रहा था, जिनमें बढ़ते गैर-निष्पादित ऋण और तकनीकी बदलाव की जरूरत प्रमुख थी। उन्होंने इन चुनौतियों का डटकर सामना किया। उनके नेतृत्व में बैंक ने डिजिटल बैंकिंग की दिशा में तेज कदम बढ़ाए। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग को अधिक मजबूत बनाया गया। उन्होंने कर्मचारियों के लिए भी कई सुधारात्मक कदम उठाए, जिनमें महिला कर्मचारियों के लिए दो साल तक का मातृत्व अवकाश और लचीली कार्य व्यवस्था जैसी पहल शामिल थीं। इन फैसलों ने उन्हें एक संवेदनशील और दूरदर्शी नेता के रूप में पहचान दिलाई। अरुंधति भट्टाचार्य का मानना है कि नेतृत्व का अर्थ केवल आदेश देना नहीं, बल्कि टीम के साथ मिलकर आगे बढ़ना होता है। वे हमेशा कर्मचारियों को प्रेरित करती थीं कि वे बदलाव को स्वीकार करें और नई तकनीकों को अपनाने से न डरें।

गिरती साख और आत्ममंथन का समय

देवेंद्रनाथ जैसवार

लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। इसका दायित्व केवल समाचार देना नहीं, बल्कि सत्ता से सवाल करना, जनता की आवाज बनना और सत्य को सामने लाना भी है। लेकिन आज भारत की मुख्यधारा की मीडिया को लेकर समाज में अविश्वास का माहौल बढ़ता दिखाई दे रहा है। लोग यह सवाल पूछने लगे हैं कि क्या मीडिया वास्तव में जनहित की प्रहरी है या फिर वह किसी न किसी राजनीतिक, आर्थिक या वैचारिक खेमे की प्रवक्ता बनती जा रही है।

दुनिया के 180 देशों में प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया की स्थिति का आकलन किया जाता है। इस सूची में भारत का स्थान 161वां होना केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी है। जिस देश की पत्रकारिता कभी लोकतंत्र की सबसे मजबूत आवाज मानी जाती थी, उसी देश की मीडिया आज वैश्विक सूचकांकों में इतनी नीचे खिसक जाए, तो यह आत्ममंथन का विषय बन जाता है। यह स्थिति किसी एक दिन में नहीं बनी, बल्कि लंबे समय से जमा हो रही कमजोरियों का परिणाम है।

लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। इसका दायित्व केवल समाचार देना नहीं, बल्कि सत्ता से सवाल करना, जनता की आवाज बनना और सत्य को सामने लाना भी है। लेकिन आज भारत की मुख्यधारा की मीडिया को लेकर समाज में अविश्वास का माहौल बढ़ता दिखाई दे रहा है। लोग यह सवाल पूछने लगे हैं कि क्या मीडिया वास्तव में जनहित की प्रहरी है या फिर वह किसी न किसी राजनीतिक, आर्थिक या वैचारिक खेमे की प्रवक्ता बनती जा रही है।

इस स्थिति को समझने के लिए वैश्विक परिप्रेक्ष्य देखना जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हर वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करती है। इसी सूचकांक में भारत का 161वां स्थान यह बताता है कि दुनिया के कई छोटे और संसाधनहीन देशों से भी हमारी मीडिया की स्थिति कमजोर मानी जा रही है। यह तथ्य केवल आलोचना का विषय नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि पत्रकारिता की दिशा कहीं भटक तो नहीं रही। भारत में मीडिया का विस्तार बहुत बड़ा है। हजारों अखबार,

सैकड़ों समाचार चैनल और असंख्य डिजिटल मंच सक्रिय हैं। सूचना का प्रवाह पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज हो चुका है। लेकिन विडंबना यह है कि माध्यमों की संख्या बढ़ने के बावजूद भरोसा घटता जा रहा है। जब खबरों में निष्पक्षता की जगह पक्षधरता दिखाई देने लगे, जब तथ्य की जगह शोर-शराबा हावी हो जाए और जब बहस का स्तर संवाद से अधिक टकराव में बदल जाए, तब साख गिरना स्वाभाविक है।

आज कई समाचार चैनलों पर बहस के नाम पर जो दृश्य दिखाई देते हैं, वे पत्रकारिता की गरिमा को चोट पहुंचाते हैं। गंभीर मुद्दों पर शांत और तथ्यपूर्ण चर्चा के बजाय आरोप-प्रत्यारोप, चीख-पुकार और सनसनीखेज प्रस्तुति को प्राथमिकता दी जाती है। इससे दर्शकों का विश्वास कमजोर होता है और पत्रकारिता की प्रतिष्ठा भी घटती है।

यहां एक कठोर सत्य स्वीकार करना होगा—किसी भी संस्था का पतन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब पत्रकारिता का उद्देश्य जनहित से हटकर केवल टीआरपी या राजनीतिक प्रभाव तक सीमित हो जाए, तब गिरावट अवश्यंभावी हो जाती है। गलत रास्तों से सही परिणाम कभी नहीं मिलते। यदि खबरों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जाए, यदि आधे-अधूरे तथ्यों से निष्कर्ष गढ़े जाएं, तो उससे थोड़े समय के लिए लाभ मिल सकता है, लेकिन लंबे समय में उसकी कीमत साख के रूप में चुकानी पड़ती है।

आज सोशल मीडिया के विस्तार ने मीडिया के सामने नई चुनौती भी खड़ी कर दी है। पहले सूचना का प्रमुख स्रोत मुख्यधारा की मीडिया ही होती थी, लेकिन अब हर व्यक्ति अपने मोबाइल से सूचना प्रसारित कर सकता है। ऐसे समय में पारंपरिक मीडिया की सबसे बड़ी ताकत केवल उसकी विश्वसनीयता ही हो सकती है। यदि वही कमजोर पड़ जाए, तो उसकी प्रासंगिकता भी घटने लगती है। मीडिया को यह समझना होगा कि जनता का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। इसे न विज्ञापन से खरीदा जा सकता है, न प्रचार से बनाया जा सकता है। यह केवल ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारिता से ही अर्जित होता है। जब पत्रकारिता साहसपूर्वक सत्ता से सवाल करती है और साथ ही समाज के हर वर्ग की आवाज बनती है, तभी वह लोकतंत्र को मजबूत करती है।

आज समय है कि मुख्यधारा की मीडिया स्वयं से सवाल पूछे। क्या वह वही भूमिका निभा रही है जिसकी अपेक्षा लोकतंत्र करता है? यदि उत्तर नकारात्मक है, तो सुधार की शुरुआत भी उसी से करनी होगी।

अंततः यह याद रखना होगा कि किसी भी संस्था का उत्थान और पतन उसके अपने हाथों में होता है। मीडिया भी इसका अपवाद नहीं है। यदि वह सत्य, संतुलन और जनहित के मूल सिद्धांतों की ओर लौटे, तो उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से लौट सकती है। लेकिन यदि गलत रास्तों को ही सफलता का साधन माना जाएगा, तो परिणाम भी उसी के अनुरूप होंगे। यही वह सच्चाई है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता।

हमारी गीता

अर्जुन-विषाद: संघर्ष से समाधान की यात्रा

स्वामिनी निष्कलानंदा
चिन्मय मिशन कल्याण

श्रीमद भगवद गीता केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं, बल्कि आधुनिक मनुष्य के मानसिक द्वंद्व का दर्पण है। कुरुक्षेत्र के मैदान में खडा अर्जुन कोई सामान्य योद्धा मात्र नहीं, बल्कि वह हमारा प्रतिनिधि है। जीवन के रणक्षेत्र में हम सभी कभी न कभी उस स्थिति में आते हैं जहाँ सब कुछ पास होते हुए भी हम 'विषाद' यानी गहरे नैराश्य से घिर जाते हैं।

अर्जुन की स्थिति और मानवीय स्वभाव

अर्जुन के पास श्रेष्ठ धनुष था, साक्षात भगवान श्रीकृष्ण का साथ था और न्याय का पक्ष भी। इसके बावजूद, अपनों के विरुद्ध खडे होने के मोह और परिणाम के डर ने उसे भीतर से झकझोर दिया। उसने धनुष-बाण त्याग दिए और रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया। यह 'अर्जुन रोग' आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है। हम साल भर पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन परीक्षा के ऐन वक्त पर डर जाते हैं। कभी असफलता (अपयश) मिलने पर हम इतने टूट जाते हैं कि आगे बढ़ने का प्रयास ही छोड़ देते हैं। पुस्तकों को फाड़ देना या पढ़ाई से विमुख हो जाना ही वह घातक मोड़ है, जहाँ हम अपने कर्तव्य से भागने लगते हैं। असल में, अपयश कोई पाप नहीं है, बल्कि प्रयास छोड़ देना ही सबसे बड़ी हार है।

दृष्टिकोण का महत्व

अक्सर हमें लगता है कि गरीबी, बीमारी या विपरीत परिस्थितियाँ हमारे दुख का कारण हैं। परंतु सत्य यह है कि हम अभावों को अधिक महत्व देते हैं और उपलब्धियों को अनदेखा कर देते हैं। हमारे पास जो साधन हैं, यदि हम उनका सही उपयोग करना सीख लें, तो सफलता दूर नहीं है। अर्जुन की व्याकुलता हमें सिखाती है कि जब बुद्धि भ्रमित हो और मन लड़खड़ाने लगे, तो अपनी शक्ति पर अहंकार करने के बजाय शरणागति का मार्ग चुनना चाहिए।

निष्कर्ष: गीता का संदेश

अर्जुन का सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय युद्ध छोड़ना नहीं, बल्कि श्रीकृष्ण को अपना गुरु मानकर उनकी शरण में जाना था। उसने स्वीकार किया कि वह भ्रमित है और मार्गदर्शन चाहता है। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर सही ज्ञान (गीता के संदेश) की ओर बढ़ते हैं, तो दिशा और दशा दोनों बदल जाती हैं।

जीवन ऊर्जा

एफ. डब्ल्यू. डी क्लार्क : जन्म - 18 मार्च 1936 | जन्म

एफ. डब्ल्यू. डी क्लार्क (फ्रेडरिक विलेम डी क्लार्क) का जन्म 18 मार्च 1936 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ। वे 1989 से 1994 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे। उन्होंने रंगभेद नीति समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की और नेल्सन मंडेला के साथ मिलकर लोकतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। 1993 में दोनों को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। उनका निधन 11 नवम्बर 2021 को हुआ।

नेतृत्व का अर्थ है कठिन निर्णय लेने का साहस

नेतृत्व का अर्थ है कठिन निर्णय लेने का साहस। सच्चा परिवर्तन संवाद से आता है। शांति केवल समझौते से नहीं बल्कि विश्वास से बनती है। लोकतंत्र मतभेदों को सम्मान देने की कला है। न्याय के बिना शांति संभव नहीं। साहस वही है जब हम इतिहास की गलतियों को स्वीकार करें। राष्ट्र तभी आगे बढ़ता है जब लोग साथ चलें। बदलाव से डरना नहीं चाहिए।

स्वतंत्रता जिम्मेदारी भी मांगती है। सुलह ही स्थायी समाधान है। अतीत से सीखना भविष्य की कुंजी है। शक्ति का सर्वोत्तम उपयोग शांति स्थापित करना है। मतभेद दुश्मनी नहीं होते। संवाद हर संघर्ष का पहला कदम है। सहिष्णुता समाज की

असली ताकत है। कानून सबके लिए समान होना चाहिए। नेतृत्व सेवा का नाम है। राष्ट्र निर्माण धैर्य मांगता है। समझदारी संघर्ष से बड़ी होती है। लोकतंत्र धैर्य और सम्मान पर टिकता है। इतिहास हमें विनम्र बनाता है। परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। न्याय और स्वतंत्रता साथ-साथ चलते हैं। कठिन समय में भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। विविधता समाज की शक्ति है। सहमति बनाने की कला ही राजनीति है। भविष्य वही बनाता है जो आज साहस दिखाता है।

संवाद बंद होते ही संघर्ष शुरू होता है। समाज को जोड़ना नेतृत्व की जिम्मेदारी है। शांति सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। सच्ची जीत वह है जिसमें सबका सम्मान हो। राष्ट्र की ताकत उसके लोगों में होती है। जिम्मेदार नेतृत्व ही स्थिरता देता है। समझौता कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता है। मानवता हर राजनीति से ऊपर होनी चाहिए।

सर्वसिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ बिजाना शाजापुर मध्यप्रदेश

अनियंत्रित इच्छाएं और संतोष का सुख

मानवीय मन की प्रकृति सागर की अनंत लहरों के समान है, जो एक इच्छा के शांत होते ही दूसरी को जन्म दे देती है। हम अक्सर ईश्वर से अपनी अधूरी कामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि कभी-कभी बिना पात्रता के मांगी गई दुआएं ही जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन सकती हैं। एक बार एक निर्धन दंपत्ति एक सिद्ध महात्मा के पास पहुंचे, जहां उन्होंने कूड़े के ढेर पर एक सोने का चिराग पड़ा देखा। महात्मा ने चेतावनी दी कि यह तीन इच्छाएं पूरी करने वाला जादुई चिराग अत्यंत खतरनाक है और जो भी इसे ले जाता है, अंत में अपनी बर्बादी देख इसे वापस यहीं फेंक जाता है। लोभ में वशीभूत दंपत्ति ने महात्मा की बात अनसुनी कर दी और उस चिराग को अपने साथ घर ले आए ताकि अपनी दरिद्रता को सदा के लिए मिटा सकें। घर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले अपनी गरीबी दूर करने के लिए दस लाख रुपयों की मांग की। क्षण भर में दरवाजे पर दस्तक हुई और एक व्यक्ति ने रुपयों से भरा बैग और एक पत्र थमाया। दंपत्ति की खुशी उस समय मातम में बदल गई जब उन्होंने पत्र पढ़ा, जिसमें लिखा था कि एक कार दुर्घटना में उनके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई है और यह राशि उसी के हर्जाने के रूप में भेजी गई है। बेटे के खोने के गम में व्याकुल पिता ने आव देखा न ताव और चिराग से दूसरी इच्छा मांग ली कि उसका बेटा वापस आ जाए। कुछ ही देर में घर का वातावरण भयावह हो गया, बिजली के बल्ब जलने-बुझने लगे और उनका पुत्र एक प्रेत के रूप में वापस लौट आया। अपने

पंडित कैलाशचंद्र शर्मा
वैदिक सनातन संस्कृति के प्रचारक व सर्व सिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ के संस्थापक।
मो. नं. 9425980556

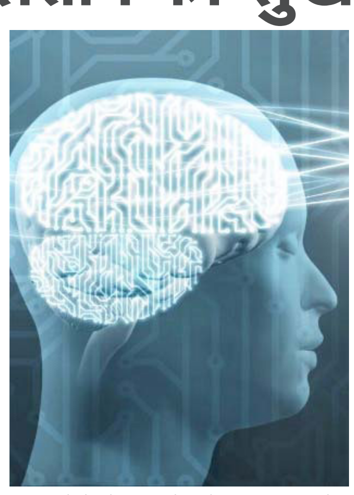

ही कलेजे के टुकड़े को उस डरावने रूप में देखकर दंपत्ति बुरी तरह कांप उठे और डर के मारे तीसरी इच्छा के रूप में उसकी मुक्ति मांग ली।

इस मर्मस्पर्शी प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि संसार में अनियंत्रित इच्छाएं केवल विनाश का मार्ग प्रशस्त करती हैं। हम भी अपनी जिंदगी में उस दंपत्ति की तरह ही हैं, जिनकी इच्छाएं बेहिसाब हैं और जो एक के पूरे होते ही दूसरी के पीछे भागने लगते हैं। प्रकृति और प्रारब्ध के नियमों के विरुद्ध जाकर प्राप्त की गई वस्तु कभी सुख नहीं दे सकती।

जिस प्रकार जादुई चिराग से मिला धन और पुनर्जीवित पुत्र केवल दुख का कारण बने, वैसे ही शॉर्टकट से मिली सफलता और बिना परिश्रम के प्राप्त वैभव मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देते हैं। अपनी हवस को शांत करने के लिए मांगी गई चीजें अंततः मानसिक शांति और आत्मिक संतोष को छीन लेती हैं।

अतः मनुष्य को जीवन में सफलता के लिए कभी जल्दबाजी नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि वास्तविक सफलता केवल निरंतर संघर्ष और धैर्य से ही प्राप्त होती है।

ईश्वर ने हमें जो भी दिया है, उसमें संतुष्ट रहना ही सुखी जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। भगवान से संसार की नश्वर वस्तुएं मांगने के बजाय संतोष, विवेक और सच्ची भक्ति मांगनी चाहिए, ताकि हम परिस्थितियों के दास न बनें। जब मन में संतोष का भाव आ जाता है, तब बड़ी से बड़ी कमी भी तुच्छ लगने लगती है। याद रखें कि अपनी मेहनत पर विश्वास रखकर प्राप्त किया गया छोटा सा अंश भी उस जादुई वैभव से कहीं श्रेष्ठ है जो हमारे अपनों की बलि या हमारे संस्कारों का पतन मांगता हो।

अपने विचार

'विपक्ष के नेता को इसकी जानकारी तो पहले भी थी। विपक्ष के नेता का दायित्व था कि वो सबसे बात करें। ना उन्होंने मेरे प्रदेश अध्यक्ष और ना ही मेरे प्रभारी और ना ही किसी अन्य लोगों से बातचीत की। उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से भी बातचीत नहीं की थी तो ये तो गलत है ना। विपक्ष के नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो सबसे साथ बैठक करें, उनको बुलाएं।

पप्पू यादव
सांसद, कांग्रेस

नीतीश कुमार का सार्वजनिक जीवन नागरिकों की सेवा और बिहार के विकास को समर्पित रहा है। राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उनके विचार और काम में हमेशा एक नयापन देखने को मिला है। राज्यसभा में उनकी उपस्थिति से बिहार के विकास को नई गति मिलेगी। साथ ही राज्य सरकार को भी वे अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे।

संजय कुमार झा
राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जेडीयू

'उत्तर प्रदेश में लॉ एंड आर्डर को ही गोली मार दी गयी है। अब भाजपाई 'आस्तीनी अपराधी' ही भाजपा सरकार का एनकाउंटर कर रहे हैं, जिन्हें भाजपाइयों ने भूमिगत तरीके से पाला-पोसा है। मुख्यनगर गोरखपुर में दिनदहाड़े हुआ ये हत्याकांड बता रहा है कि बेख़ौफ़ अपराधियों को किसका प्रश्रय

अखिलेश यादव
अध्यक्ष, सपा

वे 'सत्ता की मास्टर चाबी' हासिल करने के लिए एकजुट हों। कैसे उन्होंने नगीना में बिना किसी बड़े गठबंधन के जीत हासिल की, जो यह साबित करता है कि दलित और पिछड़ा वर्ग अब जाग चुका है ।2027 में उनकी पार्टी किंगमेकर की भूमिका में होगी।

चंद्रशेखर आजाद
प्रमुख,आजाद समाज पार्टी

अपने विचार
डीबीडी कार्यालय
ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के.के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001
indiagroundreport@gmail.com
भेज सकते हैं।

यह अखबार "माध्यम कार्पोरेट सर्विसेज लि. " के लिए प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक अरुण लाल द्वारा ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के. के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001 से प्रकाशित एवं सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, गाला नं. 4, एन.के.इंडस्ट्रियल इस्टेट, इनसाइड प्रवासी इंडिस्ट्रयल इस्टेट गेट नं. 2, गोरेगांव पू., मुंबई-63 से मुद्रित. फोन नं. 022-66555719 ईमेल : indiagroundreport@gmail.com **कार्यकारी संपादक :** अमित बृज (पी.आर.बी. अधिनियम के अंतर्गत खबरों के चयन के लिए ज्मिेदार).

ब्रीफ न्यूज़

19 मार्च से 12-डिब्बों वाली 16 उपनगरीय सेवाओं का 15-डिब्बों में परिवर्तन

मुंबई। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए वहन क्षमता बढ़ाने एवं अधिक सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से 19 मार्च, 2026 से 12-डिब्बों वाली मौजूदा 16 उपनगरीय सेवाओं को 15-डिब्बों वाली सेवाओं में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। इस विस्तार का उद्देश्य ट्रेनों की क्षमता में वृद्धि कर बढ़ती यात्री संख्या को समुचित रूप से समायोजित करना है। इससे ट्रेनों में भीड़भाड़ कम करने तथा दैनिक यात्रियों की सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन अतिरिक्त 15-डिब्बों वाली सेवाओं के शुरू होने के बाद उनकी कुल संख्या 211 से बढ़कर 227 हो जाएगी। हालांकि, उपनगरीय सेवाओं की कुल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा और यह 1414 ही रहेगी। बढ़ाई जा रही 16 सेवाओं में से 8 सेवाएं पीक आवर्स में (प्रातःकालीन पीक में 4 तथा सायंकालीन पीक में 4) परिचालित होंगी।

ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को मिला शानदार प्रतिसाद

ठाणे। जिले में आयोजित जिला स्तरीय 'सरस और मिनी सरस विक्री प्रदर्शनी' को नागरिकों से शानदार प्रतिसाद मिला। ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की कुल 51.17 लाख रुपये की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई। प्रदर्शनी में बेहतर प्रदर्शन करने वाली सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को 16 मार्च 2026 को बी.जे. हाई स्कूल, ठाणे में सम्मानित किया गया। यह प्रदर्शनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंजीत यादव के मार्गदर्शन में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, ठाणे और महाराष्ट्र स्टेट रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन मिशन (MSRLM) के संयुक्त प्रयास से वज्रेश्वरी महोत्सव के अंतर्गत आयोजित की गई। प्रदर्शनी 10 से 14 मार्च 2026 तक यशवंतराव चव्हाण मैदान, कर्णिक रोड, कल्याण (पश्चिम) में लगाई गई थी।प्रदर्शनी में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा तैयार किए गए खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प, वस्त्र और घरेलू उत्पादों के कुल 100 स्टॉल लगाए गए थे। इनमें 10 खाद्य स्टॉल और 90 हस्तशिल्प व घरेलू सामान के स्टॉल शामिल थे। इस प्रदर्शनी में 210 से अधिक महिलाओं ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। कल्याण, ठाणे और आसपास के क्षेत्रों से लगभग 12 हजार लोगों ने प्रदर्शनी का दौरा किया। लोगों ने महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को उत्साह के साथ खरीदा। प्रदर्शनी के दौरान कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को नए ग्राहकों से अतिरिक्त ऑर्डर भी मिले, जिससे उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के नए अवसर खुले।

गर्मी की छुट्टियों में 'रेल' का मेला

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

मध्य रेल ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने मुंबई, पुणे, सोलापुर, नाशिक रोड और नागपुर से देश के विभिन्न शहरों के लिए कुल 2012 ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। रेलवे ने बताया कि यात्रियों की मांग बढ़ने पर अतिरिक्त 120 विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। इससे छुट्टियों के दौरान लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

- यात्रियों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे चलाएगा 2012 समर स्पेशल ट्रेन सेवाएं
- अतिरिक्त 120 ट्रेनों का भी बैकअप तैयार

बडनेरा से नाशिक रोड के लिए दैनिक मेमू (MEMU) विशेष सेवा

विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के यात्रियों की सुविधा के लिए बडनेरा और नाशिक रोड के बीच दैनिक विशेष ट्रेन (01211/12) का संचालन 15 अप्रैल से 15 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। यह ट्रेन प्रतिदिन सुबह 10 :05 बजे बडनेरा से प्रस्थान कर उसी दिन शाम 19 :05 बजे नाशिक रोड पहुंचेगी, जबकि वापसी में नाशिक रोड से रात 21 :15 बजे निकलकर अगले दिन तड़के 04 :35 बजे बडनेरा वापस आएगी।

सोलापुर से दौंड, कलबुरगि और अनकापल्ले के लिए समर स्पेशल ट्रेनें

सोलापुर संभाग के यात्रियों के लिए रेलवे ने विशेष ग्रीष्मकालीन सेवाओं की घोषणा की है, जिसमें सोलापुर-दौंड (01461/62) और सोलापुर-कलबुरगि (01465/66) के बीच 15 अप्रैल से 15 जुलाई 2026 तक प्रतिदिन 10 डिब्बों वाली डेमू (DEMU) रैक का संचालन किया जाएगा। लंबी दूरी के यात्रियों के लिए सोलापुर-अनकापल्ले (01477/78) साप्ताहिक विशेष ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी, जो तिरुपति, विजयवाड़ा और राजमुंदरी जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों को जोड़ते हुए कुल 26 फेरे पूरे करेगी।

पुणे, दौंड और हडपसर से चलने वाली ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनें

मध्य रेल द्वारा पुणे संभाग के यात्रियों के लिए कोल्हापुर, गोरखपुर, दानापुर, नागपुर, कलबुरगि और गाजीपुर सिटी के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। पुणे-कोल्हापुर (01023/24) और पुणे-दानापुर (01449/50) जैसी ट्रेनें दैनिक रूप से चलेंगी, जबकि पुणे-गोरखपुर (01415/16) भी दैनिक सेवा प्रदान करेगी जो हडपसर के रास्ते संचालित होगी। नागपुर के लिए साप्ताहिक (01457/58) और विशेष AC साप्ताहिक (01469/70) ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, स्थानीय यात्रियों की सुविधा हेतु दौंड-कलबुरगि के बीच अनारक्षित विशेष ट्रेनें (01421/22 और 01425/26) और हडपसर-हरंगुल (01487/88) दैनिक सेवा भी उपलब्ध रहेगी। ये सभी ट्रेनें अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच सैकड़ों फेरे लगाएंगी, जिससे ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्सों और उत्तर भारत की ओर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

मुंबई से उत्तर, दक्षिण और तटीय क्षेत्रों के लिए समर स्पेशल ट्रेनें

मध्य रेल द्वारा मुंबई (CSMT, दादर और LTT) से गोरखपुर, बनारस, दानापुर, समस्तीपुर, बलिया, नागपुर, मडगांव और सोलापुर के लिए व्यापक स्तर पर ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों की घोषणा की गई है। इसके तहत CSMT-गोरखपुर (01079/80) और LTT-दानापुर (01143/44) जैसी ट्रेनें दैनिक रूप से चलेंगी, जबकि दादर-बलिया (01025/26) त्रि-साप्ताहिक और दादर-गोरखपुर (01027/28) सप्ताह में चार दिन उपलब्ध रहेंगी। कोंकण क्षेत्र के लिए CSMT-मडगांव (01171/72) और LTT-मडगांव (01119/20) साप्ताहिक सेवाएं प्रदान करेंगे, साथ ही LTT-समस्तीपुर (01043/44) विशेष AC ट्रेन भी संचालित की जाएगी। ये ट्रेनें अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच विभिन्न तिथियों पर मांग और ग्रीष्मकालीन अवकाश के आधार पर कुल सैकड़ों फेरे लगाएंगी, जिनमें यात्रियों की सुविधा हेतु AC-2 टियर, AC-3 टियर, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच शामिल किए गए हैं।

'बालरंगकर्मी' योजना के तहत बनी शॉर्ट फिल्म का अनावरण

डीबीडी संवाददाता | ठाणे

शर्मिला पिंपलोलकर ने ठाणे महानगरपालिका और साहिल आर्ट मोशन की संयुक्त 'बालरंगकर्मी' योजना के तहत तैयार शॉर्ट फिल्म 'एका बटरची बेटर गोश्त' का अनावरण किया। यह कार्यक्रम डॉ. काशीनाथ घानेकर नाट्यगृह में उत्साहपूर्ण माहौल में आयोजित किया गया। महापौर पिंपलोलकर ने कहा कि ठाणे महानगरपालिका महाराष्ट्र की ऐसी अकेली नगर निगम है, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की प्रतिभा को आगे लाने के लिए 'बालरंगकर्मी' योजना चला रही है। उन्होंने सभी बाल कलाकारों और प्रतिभागियों की सराहना की।

कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद

इस अवसर पर उपमहापौर कृष्णा पाटिल, सदन नेता हनमंत जगदाले, अतिरिक्त आयुक्त संदीप मालवी, अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे, उपायुक्त डॉ. मिताली संचेती, नगरसेवक मुकेश मोकाशी, प्रशांत जाधवर और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। फिल्म देखने के बाद सदन नेता हनमंत जगदाले ने कहा कि इसकी कहानी उन्हें अपने बचपन की याद दिलाती है। वहीं उपमहापौर कृष्णा पाटिल ने भी अपने बचपन का अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने पांचवीं कक्षा में लालटेन बनाकर लोगों को पांच रुपये में बेची थी।

छात्रों को मिला मंच और आत्मविश्वास

उपायुक्त डॉ. मिताली संचेती ने बताया कि 'बालरंगकर्मी' योजना का यह चौथा वर्ष है और इस बार छात्रों को मौका देकर लघु फिल्म बनाई गई है। इससे विद्यार्थियों को मंच और कैमरे के सामने आने का आत्मविश्वास मिला है। मंगेश देसाई (साहिल मोशन आर्ट) ने बताया कि इस वर्ष चयनित छात्रों को मौका देकर यह फिल्म तैयार की गई है। बाल कलाकार श्रेयस थोरात ने भी विद्यार्थियों के अभिनय की सराहना करते हुए अभिभावकों से बच्चों को उनकी पसंद के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की अपील की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ठाणे महानगरपालिका स्कूलों के विद्यार्थी मौजूद रहे।

इंडिया पोस्ट ने शुरू की तीन नई प्रीमियम डिलीवरी सेवाएं

- केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया लॉन्च

डीबीडी संवाददाता | मुंबई/नई दिल्ली

संचार मंत्रालय के डाक विभाग (DoP) ने देशभर में तेज और समयबद्ध डिलीवरी सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से तीन नई प्रीमियम सेवाएं — 24 स्पीड पोस्ट, 24 स्पीड पोस्ट पार्सल और 48 स्पीड पोस्ट — शुरू की हैं। इन सेवाओं का शुभारंभ केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने किया। इस अवसर पर संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी, सचिव (डाक) वंदिता कौल, महानिदेशक (डाक सेवाएं) जितेंद्र गुप्ता और सदस्य (संचालन) हरप्रीत सिंह भी उपस्थित रहे। नई प्रीमियम डिलीवरी सेवाएं फिलहाल छह प्रमुख मेट्रो शहरों — नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद — में शुरू की गई हैं। डाक विभाग के अनुसार इन सेवाओं का दायरा चरणबद्ध तरीके से टियर-1 और टियर-2 शहरों तक बढ़ाया जाएगा, जिससे देशभर में बेहतर और तेज डिलीवरी नेटवर्क तैयार किया जा सके।

24 स्पीड पोस्ट और 48 स्पीड पोस्ट की खासियत

24 स्पीड पोस्ट सेवा के तहत इन महानगरों के बीच अगले दिन (D+1) डिलीवरी की गारंटी दी जाएगी, जबकि 48 स्पीड पोस्ट सेवा में दो दिन (D+2) के भीतर डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। इन सेवाओं में रियल-टाइम ट्रैकिंग, SMS अलर्ट और OTP आधारित डिलीवरी कन्फर्मेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। समय पर डिलीवरी न होने की स्थिति में मुआवजे का प्रावधान भी रखा गया है।

पार्सल सेवा से ई-कॉमर्स और MSME को लाभ

24 स्पीड पोस्ट पार्सल सेवा विशेष रूप से समय-संवेदनशील पार्सलों के लिए शुरू की गई है। इसके तहत अगले दिन पार्सल डिलीवरी की सुविधा मिलेगी। यह सेवा ई-कॉमर्स कंपनियों, MSME और स्टार्ट-अप के लिए काफी लाभदायक मानी जा रही है। इसके अलावा रविवार और छुट्टियों के दिन भी डिलीवरी उपलब्ध रहेगी, हालांकि कुछ राष्ट्रीय अवकाशों पर यह सेवा लागू नहीं होगी।इस अवसर पर महाराष्ट्र सर्कल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल अमिताभ सिंह ने इन नई सेवाओं के लॉन्च की स्मृति में विशेष कैंसलेशन जारी किया।

ड्यूटी के दौरान मृत मोटरमैन के परिवार को मिला 1 करोड़ का बीमा

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल में ड्यूटी के दौरान एक दुर्घटना में जान गंवाने वाले वरिष्ठ मोटरमैन के परिवार को एक करोड़ रुपये की बीमा राशि प्रदान की गई। यह इस मंडल में इस प्रकार का पहला बीमा भुगतान है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के अनुसार, यह भुगतान सितंबर 2025 में भारतीय रेल और भारतीय स्टेट बैंक के बीच उन्नत रेलवे सैलरी पैकेज (RSP) योजना के तहत हुए समझौते के कारण संभव हो पाया।

समारोह में परिवार को सौंपा गया चेक

16 मार्च 2026 को आयोजित एक समारोह में पंकज सिंह (मंडल रेल प्रबंधक, मुंबई सेंट्रल मंडल) और मंजू शर्मा (मुख्य महाप्रबंधक, एसबीआई मुंबई मेट्रो सर्कल) ने दिवंगत कर्मचारी की पत्नी को एक करोड़ रुपये का चेक सौंपा। मुंबई सेंट्रल मंडल के कार्मिक विभाग ने सभी देयकों का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें एक्स-ग्रेशिया और अन्य पात्र मुआवजा भी शामिल हैं। यह बीमा राशि रेलवे की नीति के अनुसार पहले से दिए गए अन्य सेटलमेंट लाभों के अतिरिक्त है, जिससे मृत कर्मचारी के परिवार को आर्थिक सहायता मिली है।

टिटवाला-आसनगांव के बीच आज थमेंगे पहिए

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

मध्य रेल के मुंबई मंडल ने 18/19 मार्च 2026 की मध्यरात्रि को टिटवाला और आसनगांव के बीच बिजली के तारों (MSETCL 400 KV लाइन) के काम के लिए 'विशेष ट्रैफिक और पावर ब्लॉक' लेने का निर्णय लिया है। यह ब्लॉक 18 मार्च (बुधवार) और 19 मार्च (गुरुवार) की दरमियानी रात को लिया जाएगा। मुख्य काम सुबह 02:10 बजे शुरू होगा और 02:50 बजे तक (कुल 40 मिनट) चलेगा। यह काम टिटवाला और आसनगांव स्टेशनों के बीच 'अप' और 'डाउन' दोनों लाइनों पर होगा। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी (MSETCL) को रेलवे ट्रैक के ऊपर से 400 KV की हाई-वोल्टेज लाइन गुजारनी (स्ट्रिंगिंग कार्य) है। सुरक्षा के लिहाज से इस दौरान ट्रेनों की आवाजाही और बिजली की सप्लाई बंद रखना अनिवार्य है। ब्लॉक के दौरान तीन प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों को रास्ते में ही रोककर (रेगुलेट) चलाया जाएगा। अयोध्या-एलटीटी एक्सप्रेस (22104) वासिंद स्टेशन पर रोका जाएगा। यह अपने निर्धारित समय से 20-25 मिनट देरी से पहुंचेगी। शालीमार-एलटीटी एक्सप्रेस (18030) आसनगांव में रोका जाएगा।

ठाणे लोक अदालत में ट्रैफिक जुर्मानों का महा-निपटारा

- 9 हजार से ज्यादा केस खत्म
- 1.38 करोड़ का बकाया फाइन हुआ जमा

डीबीडी संवाददाता | ठाणे

ठाणे में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लिए राहत का पैगाम लेकर आई। 14 मार्च को हुई इस अदालत में हजारों पेंडिंग ई-चालान मामलों का निपटारा किया गया, जिससे न केवल अदालतों का बोझ कम हुआ बल्कि सरकार के खजाने में भी भारी रकम जमा हुई। अक्सर लोग ट्रैफिक नियम तोड़ने के बाद मोबाइल पर आए ई-चालान को नजरअंदाज कर देते हैं, जो बाद में कानूनी मुसीबत बन जाता है। ठाणे में शनिवार को आयोजित लोक अदालत में ऐसे 9,354 मामलों को आपसी समझौते के जरिए मौके पर ही सुलझा लिया गया। इससे अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या में बड़ी कमी आई है।

करोड़ों का जुर्माना सरकारी खजाने में

ट्रैफिक पुलिस उपायुक्त पंकज शिरसाट ने जानकारी दी कि ठाणे ट्रैफिक की सभी 18 यूनिट्स की मेहनत रंग लाई। इस एक दिन की कवायद में कुल 1 करोड़ 38 लाख 53 हजार 300 रुपये का बकाया जुर्माना वसूला गया। यह सरकार के राजस्व (Revenue) के लिए एक बड़ी कामयाबी है। जिन वाहन मालिकों पर जुर्माना बकाया था और जिनके खिलाफ केस दर्ज होने की नौबत आ गई थी, उनके लिए लोक अदालत एक वरदान साबित हुई। ठाणे जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की इस पहल से ड्राइवरों को कम भागदौड़ में और समझौते के आधार पर अपना रिकॉर्ड साफ करने का मौका मिला।

ई-चालान और मोबाइल का कनेक्शन

मोटर वाहन अधिनियम के तहत जब भी कोई नियम टूटता है, सीसीटीवी या डिवाइस के जरिए सीधे मालिक के मोबाइल पर ई-चालान पहुँच जाता है। लोक अदालत का मकसद उन लोगों को सबक सिखाना भी है जो इसे गंभीरता से नहीं लेते। हर तीन महीने में ऐसी अदालत लगाकर पेंडिंग मामलों को 'जीरो' करने की कोशिश की जाती है। पुलिस का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य केवल पैसा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि लोगों को यह समझाना है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना उनकी अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी है। अगर लोग नियम मानेंगे, तो न एक्सीडेंट होंगे, न जान जाएगी और न ही ई-चालान का फटका लगेगा।

12 राशिफल में देखें अपना दिन

प्रियंका जैन
97699 94439

मेष धनार्जन होगा। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। कोर्ट व कचहरी में अनुकूलता रहेगी। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। प्रमाद न करें। व्यापार-व्यवसाय में इच्छित लाभ की संभावना है। भाइयों की मदद मिलेगी। संपत्ति के लेनदेन में सावधानी रखें।

वृष संतान के कार्यों पर नजर रखें। पूंजी निवेश बढ़ेगा। प्रचार-प्रसार से दूर रहें। रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का मौका मिलेगा। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। आपके व्यवहार एवं कार्यकुशलता से अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलेगा।

मिथुन जोखिम व जमानत के कार्य न करें। लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रयत्न करें, सफलता मिलेगी। शुभ कार्यों में संलग्न होने से सुयश एवं सम्मान प्राप्त हो सकेगा। व्यापारिक निर्णय लेने में देर नहीं करें। संपत्ति के कार्य लाभ देंगे। बेरोजगारी दूर होगी।

कर्क भौतिक विकास के कार्यों को बल मिलेगा। फालतू खर्च होगा। भागीदारी के प्रस्ताव आएंगे। दिनचर्या नियमित रहेगी। यात्रा, निवेश व नौकरी मनोनुकूल रहेंगे। चोट, चोरी व विवाद आदि से हानि संभव है। जोखिम न लें। झंझटों में न पड़ें। आय में कमी होगी।

सिंह प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शत्रु शांत रहेंगे। धनार्जन होगा। आज विशेष लाभ होने की संभावना है। मेहनत का फल मिलेगा। कार्यसिद्धि से प्रसन्नता रहेगी। बुद्धि एवं मनोबल से सुख-संपन्नता बढ़ेगी। व्यापार में कार्य का विस्तार होगा। सगे-संबंधी मिलेंगे।

कन्या मान बढ़ेगा। मेहमानों का आवागमन होगा। उत्साहवर्धक सूचना मिलेगी। प्रसन्नता रहेगी। जल्दबाजी न करें। जोखिम के कार्यों से दूर रहें। पराक्रम में वृद्धि होगी। परिवार में सहयोग का वातावरण रहेगा। अभिष्ट कार्य की सिद्धि के योग हैं। उलझनों से मुक्ति मिलेगी।

तुला स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दु:खद समाचार मिल सकता है। चिंता बनी रहेगी। व्यापार-व्यवसाय में सावधानी रखें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। वास्तविकता को महत्व दें। प्रयासों में सफलता के योग कम हैं। परिवार में कलह-कलेश का माहौल रह सकता है।

वृश्चिक यात्रा, नौकरी व निवेश मनोनुकूल लाभ देंगे। भेंट आदि की प्राप्ति होगी। कोई बड़ा कार्य होने से प्रसन्नता रहेगी। व्यापार में उन्नति के योग हैं। संतान की ओर से सुखद स्थिति बनेगी। प्रयास की मात्रा के अनुसार लाभ की अधिकता रहेगी।

धनु उदर विकार के योग के कारण खान-पान पर संयम रखें। विवादों से दूर रहना चाहिए। आर्थिक प्रगति में रुकावट आ सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखें। अप्रत्याशित बड़े खर्च सामने आएंगे। कर्ज लेना पड़ सकता है, जोखिम न लें।

मकर धनार्जन होगा। प्रमाद न करें। संतान के कार्यों से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नेतृत्व गुण की प्रधानता के कारण प्रशासन व नेतृत्व संबंधी कार्य सफल होंगे। शत्रुओं से सावधान रहें। कोर्ट व कचहरी के काम निबटेंगे।

कुंभ समय की अनुकूलता का लाभ अधिकाधिक लेना चाहिए। नवीन उपलब्धियों की प्राप्ति संभव है। व्यापार-व्यवसाय अच्छा चलेगा। नई योजना बनेगी। नए अनुबंध होंगे। लाभ के अवसर बढ़ेंगे। कार्यस्थल पर परिवर्तन हो सकता है। परिवार की समस्याओं की चिंता रहेगी।

मीन रुके कार्य बनेंगे। जोखिम न लें। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। व्यवहार कुशलता एवं सहनशीलता के बल पर आने वाली बाधाओं का समाधान हो सकेगा। खानपान पर नियंत्रण रखें। नए अनुबंधों का लाभ मिलेगा। धन प्राप्ति सुगम होगी। पूछ-परख रहेगी।

बुध का रहस्यमय त्रिकोण: त्रिक भावों में बुद्धि, माया और चेतना की गहन यात्रा

जब ज्योतिष के सूक्ष्म आयामों में बुध का अध्ययन किया जाता है, तब यह केवल एक ग्रह का विश्लेषण नहीं रह जाता, बल्कि यह मानव मस्तिष्क, तंत्रिका प्रणाली और चेतना के गूढ़ रहस्यों की खोज बन जाता है। बुध को 'देवताओं का राजकुमार' कहा गया है, क्योंकि यह ज्ञान, वाणी, गणना, संचार और बुद्धि का मूल संचालक है। किंतु जब यही बुध त्रिक भावों—षष्ठ (६), अष्टम (८) और द्वादश (१२)—में स्थित होता है, तब यह साधारण बुद्धि को असाधारण गहराई में परिवर्तित कर देता है।

त्रिक भावों को सामान्यतः चुनौतीपूर्ण माना जाता है, परंतु यह वही स्थान हैं जहां आत्मा का वास्तविक विकास होता है। यहां बुध व्यक्ति को बाहरी संसार से हटाकर भीतर की जटिलताओं से परिचित कराता है। यह वह क्षेत्र है जहां 'सोचना' केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक गहन प्रक्रिया बन जाती है—एक ऐसा 'Cognitive Lab' जहां जीवन की समस्याओं का विश्लेषण होता है।

प्रियंका जैन
97699 94439

जब बुध षष्ठ भाव में स्थित होता है, तो यह व्यक्ति को एक अद्भुत विश्लेषक बना देता है। षष्ठ भाव स्वयं रोग, शत्रु और ऋण का प्रतीक है, लेकिन बुध यहां इन सभी को 'डेटा' की तरह देखता है। वह हर समस्या को छोटे-छोटे भागों में विभाजित कर उसका समाधान खोजता है। ऐसे व्यक्ति किसी भी जटिल परिस्थिति में घबराते नहीं, बल्कि उसे एक 'केस स्टडी' की तरह लेते हैं। उनका मस्तिष्क माइक्रो-लेवल पर कार्य करता है, जिससे वे उन सूक्ष्म बिंदुओं को पकड़ लेते हैं, जिन्हें सामान्य व्यक्ति नजरअंदाज कर देता है।

वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह स्थिति मस्तिष्क के 'न्यूरल सिग्नलिंग' को अत्यधिक सक्रिय करती है। व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र तेजी से प्रतिक्रिया करता है, जिससे वह समस्याओं का तुरंत विश्लेषण कर पाता है। यही कारण है कि ऐसे लोग अक्सर चिकित्सा, लेखा, कानून और डेटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। वे अपने शत्रुओं को शक्ति से नहीं, बल्कि तर्क और दस्तावेजों के माध्यम से परास्त करते हैं। यह स्थिति 'कलम की शक्ति' का सर्वोच्च उदाहरण है।

परंतु षष्ठ भाव का बुध केवल बाहरी समस्याओं तक सीमित नहीं रहता। यह व्यक्ति को अपने भीतर के दोषों को भी देखने की क्षमता देता है। वह अपने व्यवहार, अपनी आदतों और अपने विचारों का सूक्ष्म विश्लेषण करता है। यही आत्मविश्लेषण उसे धीरे-धीरे एक परिपक्व और संतुलित व्यक्तित्व में बदल देता है। जब बुध अष्टम भाव में प्रवेश करता है, तब उसकी प्रकृति और भी रहस्यमय हो जाती है। अष्टम भाव परिवर्तन, मृत्यु, रहस्य और गूढ़ विद्या का प्रतीक है। यहां बुध सतह के नीचे छिपी हुई सूचनाओं को खोजने लगता है। यह वह स्थान है जहां 'ज्ञान' शोध में बदल जाता है और 'सोचना' एक गहन ध्यान की प्रक्रिया बन जाता है।

अष्टम भाव का बुध व्यक्ति को एक खोजी बना देता है। वह हर बात के पीछे छिपे कारण को जानना चाहता है। उसकी जिज्ञासा सामान्य नहीं होती, बल्कि वह उन प्रश्नों को पूछता है, जिनके उत्तर आसान नहीं होते। यह स्थिति मस्तिष्क की 'Synaptic Plasticity' को बढ़ाती है, जिससे व्यक्ति नई सूचनाओं को गहराई से समझने और उन्हें जोड़ने की क्षमता विकसित करता है।

ऐसे लोग अक्सर ज्योतिष, मनोविज्ञान, गुप्त विज्ञान, अनुसंधान और जासूसी जैसे क्षेत्रों में रुचि रखते हैं। उनकी 'Metacognition'—अर्थात अपने विचारों के बारे में सोचने की क्षमता—बहुत विकसित होती है।

नगर निकायों को मिले 2802 पार्षद

- उत्तर प्रदेश के 761 निकायों (निगम/ पालिका/ पंचायत) में खाली थे पद
- निगम को 10, पालिका को पांच और नगर पंचायत को मिले तीन-तीन सदस्य

एजेंसी । लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार ने लंबे समय से रिक्त पड़े नगरीय निकायों के पार्षद पदों को भरते हुए बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। प्रदेश के 761 शहरी निकायों में कुल 2802 पार्षदों का मनोनयन किया गया है, जिससे स्थानीय निकायों के कार्यों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। जारी आदेश के मुताबिक, 17 नगर निगमों, 200 नगर पालिका परिषदों और 544 नगर पंचायतों में ये मनोनयन किए गए हैं।

पार्टी का लक्ष्य समग्र विकास: पंकज चौधरी

इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नव-नामित पार्षदों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी पार्षद जनसेवा और क्षेत्रीय विकास के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते हुए संगठन को और मजबूत करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी का लक्ष्य प्रदेश के समग्र विकास के साथ राष्ट्रसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाना है। नामित पार्षदों का कार्यकाल संबंधित निकायों के शेष कार्यकाल तक प्रभावी रहेगा। इस प्रक्रिया के तहत नगर निगमों में 10-10, नगर पालिका परिषदों में 5-5 और नगर पंचायतों में 3-3 पार्षद नियुक्त किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन नामों की सूची राज्य सरकार को भेजी गई थी।

चयन में सामाजिक संतुलन का विशेष ध्यान

वहीं, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने बताया कि पार्षदों के चयन में सामाजिक संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है। विभिन्न जातियों और वर्गों के साथ-साथ पार्टी के समर्पित और पुराने कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया के दौरान जिलों में पर्यवेक्षक भेजकर नामों का प्रस्ताव मंगाया गया था और इसके बाद सर्वसम्मति से अंतिम सूची तैयार की गई।

न्यूज ब्रीफ

80 हजार रिश्वत लेते इंजीनियर गिरफ्तार

देहरादून उत्तराखंड में सतर्कता विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के एक अवर अभियंता को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी उपभोक्ता से बिजली कनेक्शन और लोड बढ़ाने के नाम पर रकम वसूल रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पथरी बाग स्थित 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र में तैनात अवर अभियंता अतुल कुमार ने शिकायतकर्ता से उसकी पत्नी के नाम खरीदे गए फ्लैट में नया बिजली कनेक्शन देने और विद्युत भार बढ़ाने के एवज में 80 हजार रुपये की मांग की थी। योजनाबद्ध तरीके से टीम ने दबोचा शिकायत मिलने के बाद सतर्कता टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप ऑपरेशन चलाया। निर्धारित रणनीति के तहत जैसे ही आरोपी ने रिश्वत की रकम ली, टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सतर्कता विभाग मामले की आगे जांच कर रहा है और आरोपी से पूछताछ जारी है। विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी काम के बदले रिश्वत की मांग करता है, तो इसकी सूचना तुरंत सतर्कता विभाग को दें, ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके।

एलपीजी पर सख्ती, कालाबाजारी रोकने को 60 प्रतिष्ठानों पर छापा

पौड़ी गढ़वाल। जिले में घरेलू गैस की कालाबाजारी और अनियमितताओं पर लगाम कसने के लिए प्रशासन ने व्यापक औचक निरीक्षण अभियान चलाया। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया के निर्देश पर जिला प्रशासन और पूर्ति विभाग की संयुक्त टीमों ने गैस आपूर्ति से जुड़े प्रतिष्ठानों की जांच कर व्यवस्था का जायजा लिया। इस विशेष अभियान के तहत जनपद भर में कुल 60 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जिनमें 16 गैस गोदाम और 44 व्यावसायिक इकाइयां शामिल रहीं। जांच के दौरान अधिकारियों ने स्टॉक, वितरण प्रणाली और उपभोक्ताओं को दी जा रही सेवाओं की गहनता से परखा। गैस गोदामों पर छापे से हड़कंप क्षेत्रवार कार्रवाई में कोटद्वार में 4 गैस गोदामों की जांच की गई, जबकि दुगड्डा क्षेत्र में 1 गैस गोदाम और 8 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण हुआ। कोट-खोलाचौरी में 1 गैस गोदाम, चेलूसैंण में 5 प्रतिष्ठान, पाबौ में 1 गैस गोदाम और सतपुली में 1 गैस गोदाम सहित 10 प्रतिष्ठानों की जांच की गई।

अनियमित LPG सप्लाई से MSME सेक्टर प्रभावित

- गैस आपूर्ति में रुकावट से उद्यमियों ने जताई चिंता
- समाधान निकालने के लिए उद्योग बंधुओं ने की बैठक

एजेंसी । बरेली

औद्योगिक गैस और एलपीजी की आपूर्ति में आई बाधा ने स्थानीय उद्योगों की चिंता बढ़ा दी है। इसी मुद्दे पर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) बरेली चैप्टर की कार्यकारिणी की बैठक सोमवार देर रात एक होटल में आयोजित की गई, जिसमें उद्योगों पर पड़ने वाले संभावित असर पर विस्तार से मंथन हुआ।

केंद्र और राज्य सरकार से उम्मीद

आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गोयल ने स्थिति का विश्लेषण करते हुए कहा कि यह समस्या गैस की वास्तविक कमी से अधिक आपूर्ति तंत्र और लॉजिस्टिक्स में आई खामियों के कारण उत्पन्न हुई प्रतीत होती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियां जल्द समन्वय स्थापित कर इस संकट का समाधान निकालेंगी।

सास और साले की हत्या कर भागे आरोपी से पुलिस की मुठभेड़

24 घंटे में हत्यारे का एनकाउंटर

- मुठभेड़ में बरेली पुलिस के सिपाही अनुराग और रूपेंद्र घायल

एजेंसी । बरेली

इज्जतनगर थाना क्षेत्र के रहपुरा चौधरी गांव में सास और साले की निर्मम हत्या करने वाला आरोपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। मंगलवार सुबह हुई इस कार्रवाई में पुलिस के दो सिपाही भी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के अनुसार, सोमवार को गांव में पारिवारिक विवाद सुलझाने के लिए पंचायत आयोजित की गई थी।

मंगलवार तड़के हुई पुलिस से मुठभेड़

घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए तीन टीमें गठित की थीं। मंगलवार तड़के सूचना मिली कि वह सहारा ग्राउंड के पास देखा गया है। सूचना पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की। खुद को घिरा देख आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया।

पिस्टल, कारतूस और आलाकत्ल बरामद

घायल अवस्था में उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल, कारतूस और हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया है। मुठभेड़ के दौरान सिपाही अनुराग और रूपेंद्र घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। एसएसपी ने यह भी बताया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है। वर्ष 2009 में अपने सगे मामा की हत्या के मामले में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

आपदा प्रबंधन का गुर सीखने UK पहुंचे श्रीलंकाई अफसर

- श्रीलंका के दल में सिविल सेवा के 40 अफसर शामिल

एजेंसी । देहरादून

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्तराखंड की व्यवस्थाओं और तकनीकी पहलों को समझने के उद्देश्य से श्रीलंका के 40 सिविल सेवा अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को राज्य आपदा प्रबंधन तंत्र के अध्ययन दौरे पर देहरादून पहुंचा। इस दौरान अधिकारियों ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया।

कार्यक्रम में India Meteorological Department के वैज्ञानिक डॉ. रोहित थपलियाल ने मौसम पूर्वानुमान और मल्टी-लेयर चेतावनी प्रणाली पर प्रस्तुतिकरण दिया। वहीं Uttarakhand Landslide Mitigation and Management Centre के निदेशक डॉ. शांतनु सरकार ने भूस्खलन जोखिम प्रबंधन पर राज्य में किए जा रहे वैज्ञानिक प्रयासों की जानकारी दी।

मार्निंग वॉक पर निकले भाजपा नेता की हत्या

एजेंसी । गोरखपुर

शहर के चिलुआताल थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब वार्ड नंबर 14 बरगदवा में भाजपा नेता राजकुमार चौहान की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना ने न सिर्फ इलाके को दहला दिया, बल्कि स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश भी भड़का, जिसके चलते सोनौली मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया गया। जानकारी के अनुसार, राजकुमार चौहान रोज की तरह सुबह टहलने निकले थे।

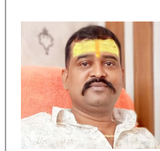

इसी दौरान पहले से घात लगाए चार हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की और करीब सौ मीटर तक दौड़े, लेकिन हमलावरों ने पीछा कर उन्हें फिर से घेर लिया और सीने, सिर व हाथों पर कई वार किए। शरीर निष्क्रिय होने तक गोदते रहे चाकू हमलावर तब तक मौके पर डटे रहे, जब तक उन्हें यह यकीन नहीं हो गया कि चौहान की मौत हो चुकी है। इसके बाद वे फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें तत्काल बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

STF से मुठभेड़ में दो कुख्यात ढेर, जवान शहीद

- मोतिहारी में हुई मुठभेड़, नेपाली नंबर से दी थी पुलिस को धमकी

एजेंसी । मोतिहारी

बिहार के मोतिहारी जिले में सोमवार देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ ने गंभीर मोड़ ले लिया। चकिया थाना क्षेत्र के रामडीहा गांव में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दो कुख्यात अपराधी मार गिराए गए, जबकि एक बहादुर जवान ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा दी। शहीद जवान की पहचान श्रीराम यादव के रूप में हुई है। वहीं मारे गए अपराधियों की पहचान कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे के रूप में की गई है, जो चकिया क्षेत्र के निवासी थे। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत कई आपराधिक मामले दर्ज थे और हाल ही में उन्होंने पुलिस अधिकारी को धमकी भी दी थी।

पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग

घेराबंदी के दौरान खुद को फंसा देख अपराधियों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस और STF ने भी मोर्चा संभाला और दोनों ओर से कुछ समय तक गोलीबारी होती रही। इस मुठभेड़ में कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे को गोली लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि, उनके कुछ साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहे। घटना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और डीआईजी सहित कई उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे।

फरार की तलाश में सर्च आपरेशन

घटना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और डीआईजी सहित कई उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। फरार अपराधियों की तलाश में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस मुठभेड़ में एक जवान के शहीद होने से पुलिस विभाग में शोक की लहर है। फिलहाल पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है।

पटना-गया-डोभी NH बनेगा ग्रीन कारिडोर

- 65 किमी तक लगाए जाएंगे फलदार पेड़

एजेंसी । पटना

बिहार में पर्यावरण संरक्षण को आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ने की दिशा में एक अहम पहल की जा रही है। पटना-गया-डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग को 'ग्रीन कॉरिडोर' के रूप में विकसित करने की व्यापक योजना तैयार की गई है, जिसके तहत सड़क किनारे बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की इस परियोजना के अंतर्गत गया वन प्रमंडल क्षेत्र में करीब 65 किलोमीटर लंबाई में 21 हजार से अधिक पौधे लगाए जाएंगे।

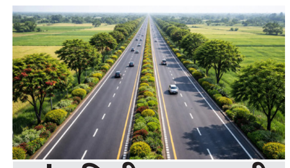

पांच किमी तक एक ही प्रजाति के पेड़

परियोजना के तहत हर पांच किलोमीटर पर एक समान प्रजाति के फलदार पौधे लगाए जाएंगे, जिससे एक व्यवस्थित और आकर्षक हरित पट्टी विकसित की जा सके। इसमें आम, अमरूद, जामुन, लीची, कटहल, आंवला, बेल, नींबू और सहजन जैसे फलदार पौधों के साथ-साथ नीम, बरगद, पीपल और पाकड़ जैसे छायादार वृक्ष शामिल किए गए हैं।

जनभागीदारी से बनाएंगे हरित मॉडल

इस परियोजना की विशेषता इसका जनभागीदारी मॉडल है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों—जैसे मुखिया, पंचायत सदस्य, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य, विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों—के सहयोग से इसे जमीन पर उतारा जाएगा। किसानों की रैयती जमीन को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जिससे सामुदायिक खेती को बढ़ावा मिलेगा और उन्हें अतिरिक्त आमदनी का साधन प्राप्त होगा। परियोजना की समीक्षा करते हुए विभागीय मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने अधिकारियों को विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

व्यापार जगत

25 लाख हुई ग्रेच्युटी की सीमा

- एडेड स्कूल स्टाफ को योगी की सौगात, हजारों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

एजेंसी । लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार ने सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के हित में अहम निर्णय लेते हुए उनकी ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ा दी है। अब सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली ग्रेच्युटी राशि 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। शासन की ओर से 16 मार्च को जारी आदेश के अनुसार, यह बढ़ी हुई सीमा तभी लागू होगी जब महंगाई भत्ता (डीए) मूल वेतन का 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाएगा। इस प्रावधान के लागू होने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को पहले की तुलना में अधिक आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी।

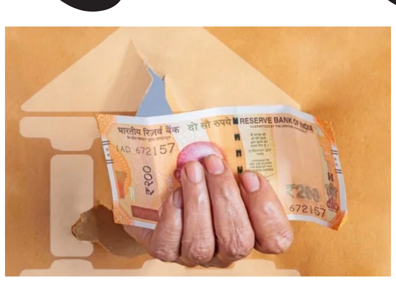

डीए 50% या अधिक की बाध्यता

शासन की ओर से 16 मार्च को जारी आदेश के अनुसार, यह बढ़ी हुई सीमा तभी लागू होगी जब महंगाई भत्ता (डीए) मूल वेतन का 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाएगा। सरकार के इस निर्णय को शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है। जो सेवानिवृति के बाद उनकी आर्थिक स्थिति को अधिक सुदृढ़ बनाने में मदद करेगा।

सहायता प्राप्त स्कूलों को भी लाभ

माध्यमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट) के प्रवक्ता ओम प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि यह सुविधा राज्य सरकार के कर्मचारियों को पहले से उपलब्ध थी, लेकिन अब इसे सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों पर भी लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से प्रदेश के करीब 50 हजार शिक्षक और कर्मचारी लाभान्वित होंगे। शासन की ओर से 16 मार्च को जारी आदेश के अनुसार, यह बढ़ी हुई सीमा तभी लागू होगी जब महंगाई भत्ता (डीए) मूल वेतन का 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाएगा। इस प्रावधान के लागू होने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को पहले की तुलना में अधिक आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में वेतन समिति 2016 की सिफारिशों के आधार पर इन विद्यालयों में पेंशन, ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन से जुड़े नियमों में संशोधन किया गया था। उस समय ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये निर्धारित की गई थी, जो अब बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।

ईरान तनाव से उछला कच्चा तेल, ब्रेंट 103 डॉलर के पार

- सप्लाई चेन पर संकट गहराने की आशंका

एजेंसी । नई दिल्ली

वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक दिन की गिरावट के बाद फिर तेज उछाल देखने को मिला है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, खासकर ईरान से जुड़े घटनाक्रम के कारण सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है, जिसका सीधा असर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार पर पड़ा है। ताजा कारोबार में ब्रेंट क्रूड करीब 3.1 फीसदी की तेजी के साथ 103.28 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हालात और बिगड़ते हैं तो कच्चे तेल की कीमतों में और उछाल आ सकता है, यहां तक कि यह 200 डॉलर प्रति बैरल तक भी पहुंच सकता है। हालांकि, इससे पहले पिछले सत्र में तेल कीमतों में गिरावट आई थी, जब ब्रेंट में करीब 2.8 फीसदी और डब्ल्यूटीआई में 5.3 फीसदी की कमी दर्ज की गई थी। उस समय कुछ जहाजों की आवाजाही बहाल होने से राहत की उम्मीद जगी थी। बाजार विश्लेषकों के अनुसार, ईरान से जुड़े तनाव के कारण सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ा है, जिससे कीमतों

में अस्थिरता बनी हुई है। हाल ही में कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई थीं, जो पिछले चार वर्षों का उच्च स्तर था। तेल कीमतों को नियंत्रित करने के प्रयास में ने 400 मिलियन बैरल कच्चा तेल बाजार में जारी करने पर सहमति जताई है। हालांकि, एजेंसी का मानना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए यह कदम पर्याप्त नहीं है।

दमदार फीचर्स के साथ लुभाने आई रेनो डस्टर

- नए लुक वाली डस्टर की शुरुआती कीमत 10.49 लाख रुपये

एजेंसी । नई दिल्ली

फ्रांसीसी ऑटोमोबाइल कंपनी Renault ने भारतीय बाजार में अपनी चर्चित एसयूवी 'डस्टर' को नए अवतार में लॉन्च कर दिया है। आकर्षक डिजाइन और आधुनिक फीचर्स से लैस इस मिड-साइज एसयूवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपये रखी गई है, जबकि डिलीवरी भी देशभर में तत्काल प्रभाव से शुरू कर दी गई है।

दो इंजन के विकल्प मौजूद

इंजन और ट्रांसमिशन की बात करें तो इस एसयूवी में टर्बो टीसीई 1.0 लीटर और 1.6 लीटर के दो इंजन विकल्प दिए गए हैं। इसे मैनुअल के साथ-साथ ड्यूल-क्लच ट्रांसमिशन (DCT) विकल्प में भी पेश किया गया है। यह मॉडल कुल पांच वेरिएंट में उपलब्ध है। लॉन्च ऑफर के तहत कंपनी ने 31 मार्च तक बुकिंग कराने वाले ग्राहकों को शुरुआती वेरिएंट 10.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में उपलब्ध कराने की घोषणा की है।

फीचर्स के लिहाज से नई डस्टर को फुल एलईडी लाइटिंग, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) और 360 डिग्री कैमरा जैसे आधुनिक तकनीकी फीचर्स से लैस किया गया है। साथ ही कंपनी इस पर सात साल की वारंटी भी दे रही है, जो ग्राहकों के भरोसे को और मजबूत करती है। कंपनी ने बताया कि नई डस्टर देशभर में अपने 350 से अधिक बिक्री केंद्रों और 450 से ज्यादा सर्विस नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध होगी। कंपनी के अनुसार, नई डस्टर को भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

जेपी एसोसिएट्स केसः अडानी की समाधान योजना को मंजूरी

एजेंसी । नई दिल्ली

कर्ज में डूबी कंपनी के समाधान की दिशा में एक अहम प्रगति हुई है। अडानी एंटरप्राइजेज ने जानकारी दी है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने जयप्रकाश एसोसिएट्स के लिए उसकी समाधान योजना को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने मंगलवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि 17 मार्च, 2026 को ट्रिब्यूनल ने मौखिक आदेश के माध्यम से इस योजना को स्वीकृति प्रदान की।

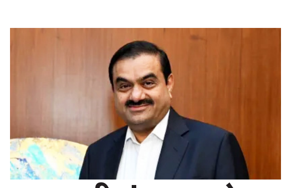

अडानी एंटरप्राइजेज सफल बोलीदाता

गौरतलब है कि अदानी एंटरप्राइजेज को पहले ही इस प्रक्रिया में सफल बोलीदाता घोषित किया जा चुका था। नवंबर 2025 में कर्जदाताओं की समिति ने भी इस योजना को मंजूरी दे दी थी। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि इस योजना को वह स्वयं, अपनी सहयोगी कंपनियों या विशेष प्रयोजन इकाइयों के माध्यम से लागू कर सकती है।

जून 2024 में शुरू हुई थी दिवालिया प्रक्रिया

जेपी समूह की प्रमुख कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स पर करीब 57,185 करोड़ रुपये का भारी कर्ज है। इसके प्रमुख कर्जदाताओं में National Asset Reconstruction Company भी शामिल है। कंपनी को जून 2024 में दिवालिया प्रक्रिया में शामिल किया गया था, जब NCLT की इलाहाबाद पीठ ने इस संबंध में आदेश जारी किया था। कारोबारी दृष्टि से देखें तो जयप्रकाश एसोसिएट्स सीमेंट, बिजली, होटल, निर्माण और रियल एस्टेट जैसे विविध क्षेत्रों में सक्रिय रही है, लेकिन बढ़ते कर्ज के चलते इसे Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) के तहत प्रक्रिया में लाया गया। दूसरी ओर, जयप्रकाश एसोसिएट्स ने साफ किया है कि इस पुनर्गठन योजना में शेयरधारकों को कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। कंपनी की परिसंपत्तियों का मूल्य इतना नहीं है कि कर्जदाताओं की पूरी देनदारी चुकाई जा सके, इसलिए इक्विटी निवेशकों के लिए एग्जिट वैल्यू शून्य तय की गई है।

वैश्विक तनाव के बीच हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत: पीयूष गोयल

एजेंसी । नई दिल्ली

वैश्विक अस्थिरता और पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को लोकसभा में यह भरोसा जताते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बावजूद भारत की आर्थिक स्थिति स्थिर और सशक्त बनी हुई है। प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापारिक साझेदारी बढ़ाने को लेकर दुनिया के विभिन्न देशों में उत्साह दिखाई दे रहा है। पिछले तीन वर्षों में भारत ने 38 देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं।

चेन्नई को मिल गया धौनी का वारिस!

- एमएस का संभवत: यह अंतिम आईपीएल सत्र
- संजू सैमसन बनेंगे चेन्नई के नए थाला

एजेंसी । चेन्नई

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए आईपीएल 2026 केवल एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि एक 'युग के अंत' और 'नए युग के आरंभ' की कहानी है। महेंद्र सिंह धौनी की विरासत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी अब संजू सैमसन के कंधों पर नजर आ रही है। पिछले सीजन (2025) की नाकामी को पीछे छोड़कर 'येलो आर्मी' एक नई पहचान गढ़ने के लिए तैयार है। एमएस धौनी ने चेन्नई को केवल 5 ट्रॉफियां ही नहीं दीं, बल्कि एक ऐसी संस्कृति दी जो परिवार की तरह है। 2026 का सत्र धौनी के करियर का संभावित आखिरी पड़ाव माना जा रहा।

संजू सैमसन: प्रतिभा, परिपक्वता और चुनौती

सीएसके प्रबंधन ने संजू सैमसन पर दांव लगाकर यह साफ कर दिया है कि वे भविष्य की ओर देख रहे हैं। सैमसन में वह 'कूल' अंदाज और आक्रामक बल्लेबाजी है जो धौनी की याद दिलाती है। हालांकि, सैमसन के लिए सबसे बड़ी चुनौती धौनी जैसी निरंतरता और प्रशंसकों का अटूट भरोसा हासिल करना होगी।

2025 की कड़वी यादें और सुधार

पिछला सीजन चेन्नई के लिए किसी बुरे सपने जैसा था, जहाँ टीम अंक तालिका में सबसे नीचे रही। हालांकि, शिवम दुबे (357 रन) और मिस्ट्री स्पिनर नूर अहमद (24 विकेट) ने व्यक्तिगत तौर पर प्रभावित किया था। इस बार हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने अपनी रणनीति में 'आक्रामकता' जोड़ी है ताकि टीम फिर से टॉप पर पहुँच सके। इस बार की टीम में अनुभवी और युवाओं का संतुलन पिछले साल की तुलना में बेहतर दिख रहा है।

चैंपियन
2010, 2011, 2018, 2021, 2023

चेपॉक की नई संस्कृति

चेन्नई के फैंस (येलो आर्मी) का प्यार जीतना आसान नहीं है। वहां प्रदर्शन से ज्यादा 'जुड़ाव' की अहमियत है। धौनी ने जो 'येलो लव' कमाया है, उसे कायम रखना सैमसन के लिए अग्निपरीक्षा जैसा होगा। टीम अब केवल अनुभव के भरोसे नहीं, बल्कि युवा जोश के साथ मैदान में उतरेगी।चेपॉक का मैदान अपने सबसे लाडले खिलाड़ी को विदा करने के लिए तैयार है, लेकिन सवाल वही है—धौनी के बाद कौन?

इस बार चेन्नई ने क्या बदला

1. रणनीति में बदलाव

- 'डैड्स आर्मी' की छवि से बाहर निकलते हुए अब टीम युवा और आक्रामक कॉम्बिनेशन पर ध्यान दे रही है।
- उर्विल पटेल, आयुष म्हात्रे और डेवॉल्ड ब्रेविस जैसे खिलाड़ियों को जोड़कर टीम में नई ऊर्जा लाई गई है।

2. नीलामी में बड़ा दांव

- कोच स्टीफन फ्लेमिंग की रणनीति में टीम ने प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा पर बड़ा निवेश किया।
- प्रशांत वीर को रवींद्र जडेजा के विकल्प के रूप में तैयार किया जा रहा है।
- कार्तिक शर्मा अपनी पावर हिटिंग से मध्य क्रम को मजबूती देंगे।
- म्हात्रे (18), कार्तिक (19), वीर (20) और ब्रेविस (22) के आने से टीम की औसत उम्र घटेगी।

न्यूजीलैंड की जीत में चमके कॉन्वे और सीयर्स

एजेंसी । हैमिल्टन

हैमिल्टन में खेले गए दूसरे टी-20 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने शानदार वापसी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 68 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही कीवी टीम ने पांच मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत संभली हुई रही। सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉन्वे (60) ने एक छोर मजबूती से थामे रखा। हालांकि दूसरे छोर पर टॉम लैथम (11) और रॉबिंसन सस्ते में निपट गए, लेकिन कॉन्वे की अर्धशतकीय पारी ने टीम को मुश्किल से निकाला और स्कोरबोर्ड को चलायमान रखा। मध्यक्रम में निकी केली (21) और कप्तान मिचेल सेंटनर (20) ने कुछ अच्छे हाथ दिखाए, लेकिन वे बड़ी पारी में तब्दील नहीं हो सके। एक समय टीम दबाव में दिख रही थी, लेकिन अंत में जोश क्लार्कसन (नाबाद 26) और कोल (नाबाद 18) ने तेज बल्लेबाजी कर टीम का स्कोर 6 विकेट पर 175 रन तक पहुँचा दिया।176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। कीवी गेंदबाजों ने शुरुआत से ही इतना दबाव बनाया कि कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं सका। टीम के शीर्ष और मध्यक्रम के बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छूने के लिए भी संघर्ष करते नजर आए।

कोलकाता के अधिकतर मैचों से बाहर रहेंगे राणा

- घुटने की सर्जरी के बाद 'रिहैब' में हैं स्टार गेंदबाज

एजेंसी । कोलकाता

आईपीएल 2026 के आगाज से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खेमे से एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है। टीम के स्टार तेज गेंदबाज हर्षित राणा घुटने की सर्जरी के कारण आईपीएल के आगामी सीजन के बड़े हिस्से से बाहर हो सकते हैं। डिफेंडिंग चैंपियन के लिए यह दोहरा झटका है, क्योंकि उनके अन्य मुख्य गेंदबाज भी फिटनेस समस्याओं से जूझ रहे हैं। हर्षित राणा को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी-20 विश्व कप के अभ्यास मैच के दौरान चोट लगी थी। चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें घुटने की सर्जरी करवानी पड़ी। 'ईएसपीएनक्रिकइंफो' के अनुसार, वे फिलहाल 'रिहैबिलिटेशन' (रिकवरी प्रक्रिया) से गुजर रहे हैं। बीसीसीआई ने अभी उनकी वापसी के लिए कोई हरी झंडी नहीं दी है, जिसका मतलब है कि वे टूर्नामेंट के शुरुआती और शायद बीच के कई मैच मिस करेंगे। उनकी कमी पूरी करने के लिए अब केकेआर को ऑक्शन में लिए गए अन्य विकल्पों की ओर देखना होगा। पथिराना और हर्षित दोनों का बाहर होना टीम के 'बॉलिंग कॉम्बिनेशन' को पूरी तरह बिगाड़ सकता है। पिछले सीजन में हर्षित राणा ने डेथ ओवर्स और पावरप्ले में शानदार गेंदबाजी की थी।

पथिराना की फिटनेस पर भी बादल

मुसीबत अकेले नहीं आती। श्रीलंका के 'यॉर्कर किंग' मथीशा पथिराना भी पिंडली (Calf) की चोट से जूझ रहे हैं। पथिराना का शुरुआती मैचों में खेलना संदिग्ध है। ऐसे में केकेआर का पेस अटैक (तेज गेंदबाजी आक्रमण) टूर्नामेंट की शुरुआत में काफी कमजोर नजर आ रहा है।

सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी का सम्मान

मैदान से बाहर होने के बावजूद हर्षित राणा चर्चा में हैं। रविवार को हुए बीसीसीआई नमन पुरस्कार समारोह में उन्हें 'सर्वश्रेष्ठ उदीयमान अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी' के पुरस्कार से नवाजा गया। फैंस उम्मीद कर रहे थे कि यह युवा सनसनी आईपीएल में अपनी रफ्तार का जलवा दिखाएगी, लेकिन फिलहाल उन्हें डगआउट में ही बैठना होगा।

29 मार्च को 'अग्निपरीक्षा'

केकेआर अपना अभियान 29 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ शुरू करेगी। टीम बुधवार से अपना अभ्यास सत्र शुरू करने वाली है। मुख्य गेंदबाजों की अनुपस्थिति में कोच और कप्तान को अब बेंच स्ट्रेंथ और अन्य भारतीय तेज गेंदबाजों पर निर्भर रहना होगा।

फीफा विश्व कप 2026

ईरान का अमेरिका में खेलने से इनकार

एजेंसी । वॉशिंगटन

ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध से फुटबॉल जगत भी अछूता नहीं रहा है। इस साल अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा की संयुक्त मेजबानी में FIFA विश्व कप खेला जाना है, जिससे ईरान पीछे हटने की बात कह चुका है। अब खबर है कि ईरान विश्व कप में सशर्त खेलने के लिए तैयार हुआ है। ईरान की मांग है कि उनकी टीम इस वैश्विक संस्करण में तब ही हिस्सा लेगी, जब उनके मैच अमेरिका की जगह मैक्सिको में खेले जाएंगे।

ईरान ने मैक्सिको में अपने मैच खेलने की जताई इच्छा

ईरानी फुटबॉल प्रमुख मेहदी ताज ने देश के मैक्सिकन दूतावास के एक्स अकाउंट के जरिए कहा, 'जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया है कि वे ईरानी राष्ट्रीय टीम की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, तो हम निश्चित रूप से अमेरिका नहीं जाएंगे।' उन्होंने आगे कहा, 'हम अभी FIFA के साथ बातचीत कर रहे हैं कि विश्व कप में ईरान के मैच मैक्सिको में करवाए जाएं।'

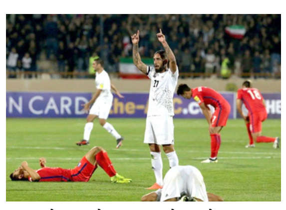

पिछले हफ्ते ईरान के खेल मंत्री अहमद दोन्यामाली ने टूर्नामेंट से हटने का ऐलान किया था। उन्होंने सरकारी टेलीविजन पर कहा था, ''यह देखते हुए कि इस भ्रष्ट सरकार (अमेरिका की) ने हमारे नेता की हत्या कर दी है, हम किसी भी हालत में फुटबॉल के विश्व कप में हिस्सा नहीं ले सकते।

लॉस एंजिलिस ओलंपिक में चार दिन पहले शुरू होंगे फुटबॉल मुकाबले

एजेंसी । लॉस एंजिलिस

लॉस एंजिलिस 2028 ओलंपिक में फुटबॉल स्पर्धाओं का आगाज मुख्य उद्घाटन समारोह से चार दिन पहले, यानी 21 जुलाई से हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) द्वारा तैयार किए गए इस नए कार्यक्रम की खास बात यह है कि खिलाड़ियों को पिछले आयोजनों की तुलना में विश्राम के लिए दो अतिरिक्त दिन मिलेंगे। इन मैचों का आयोजन अमेरिका के सात प्रमुख शहरों में किया जाएगा।

शुरुआती कुछ मैचों में नहीं खेल पाएंगे जोश हेजलवुड और पैट कमिंस

एजेंसी । मुंबई

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होनी है, जिसके लिए सभी टीमें अपनी-अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस बीच खबर है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के जोश हेजलवुड और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के पैट कमिंस आगामी सीजन के शुरुआती कुछ मैचों से बाहर रहने वाले हैं। दरअसल, ये दोनों ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज फिलहाल फिटनेस हासिल करने में क्रम में रिहैब कर रहे हैं।

हेजलवुड हैमस्ट्रिंग और अकिलीज टेंडन की चोट के बाद रिकवरी कर रहे हैं, जबकि कमिंस लोअर बैक की चोट से वापसी करने के लिए प्रयासरत हैं। ये दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की मेडिकल टीम की निगरानी में रिहैब कर रहे हैं।

IPL 2025 में शानदार रहा था हेजलवुड का प्रदर्शन

IPL 2025 का खिताब RCB ने जीता था और हेजलवुड इस विजेता टीम के सदस्य थे। पिछले सीजन में हेजलवुड ने RCB के लिए 12 मैच खेले, जिसमें 17 .54 की उम्दा औसत और 8 .77 की इकॉनमी रेट के साथ 22 विकेट लिए थे। हेजलवुड IPL 2025 की समाप्ति के बाद संयुक्त रूप से तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे।

कमिंस की गैरमौजूदगी में ईशान किशन कर सकते हैं SRH की कप्तानी

रिपोर्ट के अनुसार, कमिंस की गैरमौजूदगी में शुरुआती कुछ मैचों में SRH की कप्तानी ईशान किशन करते हुए नजर आ सकते हैं। किशन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड की कप्तानी कर चुके हैं और इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने टी–20 विश्व कप 2026 में 9 पारियों में 35 .22 की औसत और 193 .29 की स्ट्राइक रेट से 317 रन बनाए थे।

बॉ ली वु ड

गिप्पी ग्रेवाल को जान से मारने की धमकी

पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल को कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। इस संबंध में सुखबीर सिंह बादल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर यह दावा किया और एक कथित ऑडियो भी जारी किया है। सुखबीर बादल द्वारा साझा किए गए ऑडियो में एक व्यक्ति खुद को गोल्डी बराड़ बताते हुए गिप्पी ग्रेवाल को धमकी देता सुनाई दे रहा है। कॉल करने वाला व्यक्ति चेतावनी देता है कि यदि गायक ने उसके संदेश को नजरअंदाज किया तो वह "गोलियां नहीं संभाल पाएगा।" हालांकि अधिकारियों की ओर से इस ऑडियो की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सुखबीर बादल ने इस मुद्दे को सीधे भगवंत मान के सामने उठाते हुए पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि गिप्पी ग्रेवाल को धमकी ऐसे समय में मिली है जब हाल ही में उनकी सुरक्षा वापस ली गई थी। सुखबीर बादल ने अपने पोस्ट में कहा कि गिप्पी ग्रेवाल हाल ही में उनके बादल स्थित आवास पर उनसे मिलने आए थे, जिसके बाद उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर हो गई है। सुखबीर बादल ने इस मामले को सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जोड़ते हुए कहा कि पंजाब पहले ही अपने एक बड़े कलाकार को खो चुका है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर गिप्पी ग्रेवाल के साथ कोई घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। फिलहाल इस कथित धमकी भरे ऑडियो की पुलिस या प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मामले को लेकर जांच और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

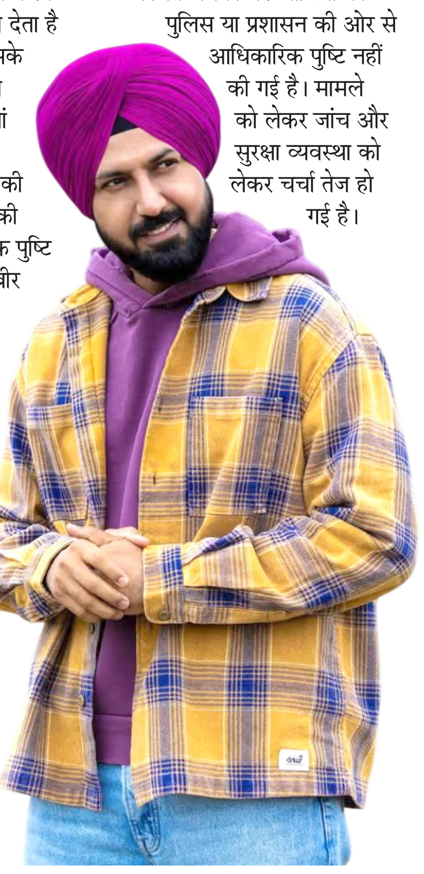

'सरके चुनर' गाने पर सरकार सख्त

नोरा फतेही और संजय दत्त का गाना 'सरके चुनर' रिलीज के बाद से ही लगातार विवादों में घिरा हुआ है। गाने के बोल और डांस स्टेप को लेकर इसकी आलोचना की जा रही है और इस पर बैन लगाने की मांग की जा रही है। अब सरकार ने सेंसर बोर्ड को इस गाने को सभी प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाने और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सीबीएफसी को गाने पर सख्त कार्रवाई करने और आरोपों के सही पाए जाने पर सभी मीडिया प्लेटफॉर्म से गाने को हटाने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि फिल्मों और संगीत वीडियो में अश्लील या आपत्तिजनक सामग्री की निगरानी को और सख्त किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर, सार्वजनिक तौर पर अश्लील या हानिकारक मानी जाने वाली सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए फिल्म प्रमाणीकरण नियमों में संशोधन पर भी विचार किया जा सकता है। 'सरके चुनर तेरी सरके' आगामी पैन इंडिया कन्नड़ फिल्म 'केडीः द डेविल' का हिस्सा है, जिसका निर्देशन प्रेम ने किया है। गाने के बोल डबल मीनिंग वाले हैं, जो अश्लीलता को दर्शाते हैं। गाने में नोरा फतेही के साथ संजय दत्त भी नजर आए हैं। फिल्म के आधिकारिक संगीत सहयोगी आनंद ऑडियो ने इस गीत को हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में अपलोड किया था।

ऋतिक रोशन की नई फिल्म 'मेस' का ऐलान

ऋतिक रोशन अब की दुनिया में नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने अपने बैनर फिल्म्स के तहत फिल्म मेस के लिए प्राइम वीडियो इंडिया के साथ साझेदारी की है। इस परियोजना में उनके कजिन भाई ईशान रोशन भी शामिल होंगे। ऋतिक और प्राइम वीडियो का यह दूसरा सहयोग है। इससे पहले दोनों ने पिछले साल थ्रिलर वेब सीरीज स्टॉर्म की घोषणा की थी, जिसे लेकर दर्शकों में काफी उत्साह देखा गया था। अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म कृष 4 के जरिए निर्देशन की जिम्मेदारी संभाल चुके ऋतिक अब बतौर निर्माता भी नई पारी शुरू कर रहे हैं। फिल्म 'मेस' उनके प्रोडक्शन हाउस के तहत बनने वाली एक अहम परियोजना मानी जा रही है। फिल्म का निर्देशन राजेश ए. कृष्णन करेंगे, जो पहले लूटकेस और क्रू जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। फिल्म का प्रोडक्शन जल्द शुरू होने की संभावना है। फिल्म 'मेस' की कहानी लुटेरों के एक गिरोह के इर्द-गिर्द घूमेगी, जो चोरी के इरादे से एक ऐसे व्यक्ति के घर में घुसते हैं जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से जूझ रहा होता है।कहानी में एक ही रात के भीतर हालात ऐसे मोड़ लेते हैं कि लुटेरों का गिरोह खुद ही खतरनाक स्थिति में फंस जाता है। फिल्म में कॉमेडी और अफरा-तफरी का भरपूर तड़का देखने को मिलेगा। जल्द ही इसकी कास्ट और रिलीज डेट से जुड़ी जानकारी सामने आ सकती है।

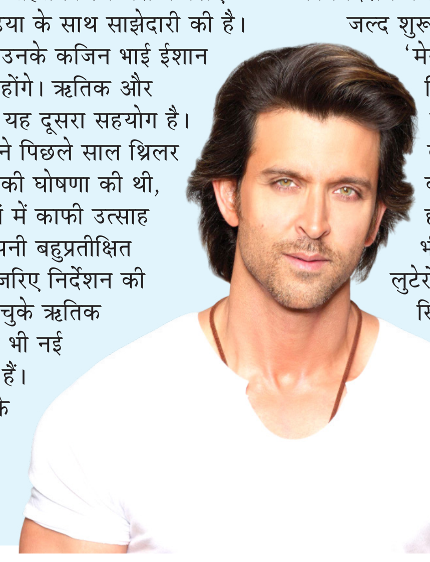

शाहरुख खान फिर रोमांटिक हीरो बनकर करेंगे वापसी

शाहरुख खान ने 2023 में पठान और जवान जैसी एक्शन-थ्रिलर फिल्मों के जरिए दमदार कमबैक किया था। इन फिल्मों में उन्होंने अपने पारंपरिक रोमांटिक हीरो की छवि से अलग अवतार दिखाया और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की। शाहरुख की अगली फिल्म किंग भी एक्शन शैली की बताई जा रही है, जिसमें वे हाई-ऑक्टेन एक्शन करते नजर आएंगे। यह फिल्म दिसंबर 2026 में रिलीज होने वाली है। ताजा खबरों के अनुसार, शाहरुख खान को एक बड़े बजट की रोमांटिक ड्रामा फिल्म के लिए संपर्क किया गया है। सूत्रों के मुताबिक अभिनेता को इसकी स्क्रिप्ट काफी पसंद आई है और वे एक बार फिर अपने रोमांटिक अंदाज में दर्शकों के सामने आने के इच्छुक हैं। सूत्रों का कहना है कि यह फिल्म उनकी पुरानी फिल्मों की तरह पारंपरिक रोमांस नहीं होगी, बल्कि उनकी उम्र के अनुरूप एक परिपक्व प्रेम कहानी होगी, जिसमें भावनाएं और गहरा ड्रामा देखने को मिलेगा। खबर है कि लगातार एक्शन फिल्मों के बाद शाहरुख कुछ समय के लिए शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं से दूरी बनाना चाहते हैं। डॉक्टरों की सलाह और पिछले कुछ वर्षों में लगी चोटों को देखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया है। सूत्रों के मुताबिक यह नई रोमांटिक ड्रामा फिल्म जनवरी या फरवरी 2027 से फ्लोर पर जा सकती है। यदि ऐसा होता है, तो शाहरुख खान एक बार फिर अपने प्रसिद्ध 'किंग ऑफ रोमांस' अवतार में दर्शकों को नजर आ सकते हैं।

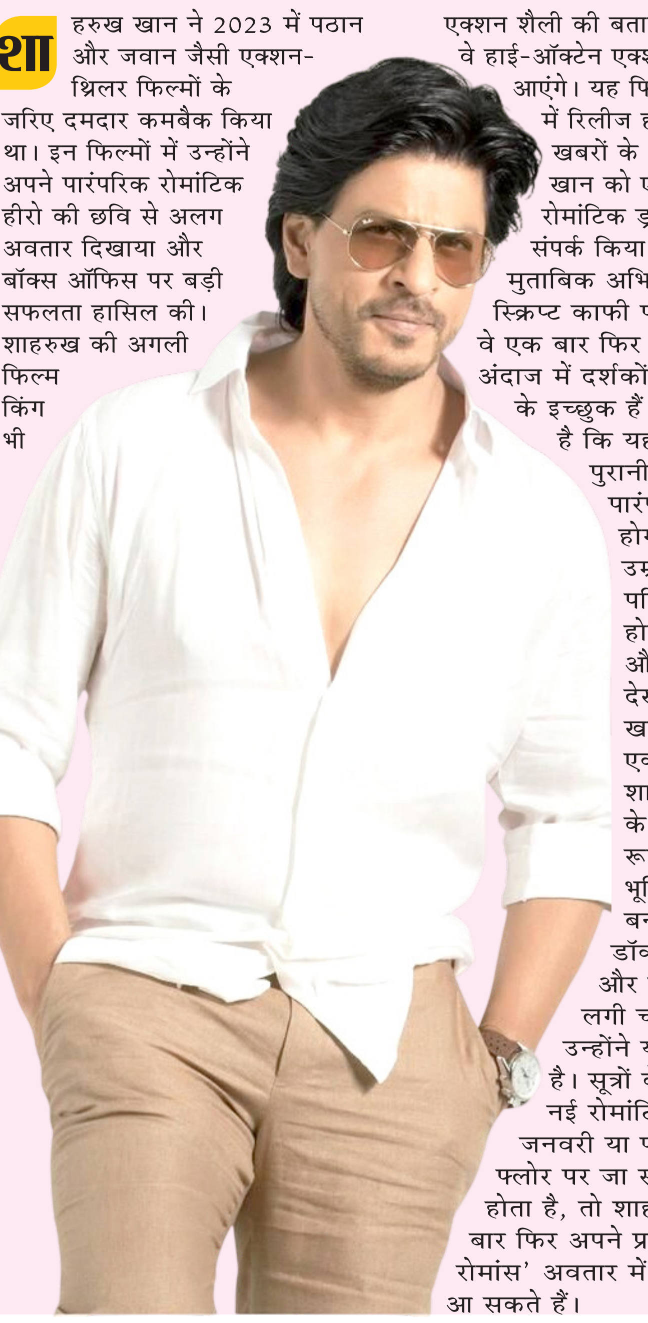

बंगाल विधानसभा चुनाव

तृणमूल ने एक ही बार में घोषित कर दिए सारे उम्मीदवार

टीएमसी ने जारी की 291 उम्मीदवारों की सूची, भवानीपुर से ममता बनर्जी और शुभेंदु की लड़ाई तय

एजेंसी | कोलकाता

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 291 सीटों के लिए पार्टी के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची के साथ ही राज्य में चुनावी मुकाबले की तस्वीर साफ होने लगी है। ममता बनर्जी ने कोलकाता के कालीघाट स्थित अपने आवास से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की और कहा कि पार्टी इस बार भी जीत की परंपरा को बनाए रखने के लिए पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरेगी। ममता बनर्जी ने उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए कहा कि पार्टी ने इस बार अनुभव और नए चेहरों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। सूची में कई मौजूदा विधायकों को फिर से मौका दिया गया है, जबकि कुछ सीटों पर नए चेहरों को उतारा गया है। खास बात यह है कि इस बार भी भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ेंगी, जहां उनका मुकाबला भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी से होने की संभावना जताई जा रही है। आइए, पहले एक नजर सूची पर डालते हैं।

भवानीपुर में क्यों अहम है मुकाबला?

दरअसल, पिछले विधानभसभा चुनाव में ममता बनर्जी दो सीटों से चुनावी मैदान में उतरी थीं। एक नंदीग्राम और दूसरी भवानीपुर विधानसभा। नंदीग्राम में ममता का मुकाबला भाजपा नेता शुभेंदु से था। यहां वो शुभेंदु से चुनाव हार गईं थीं। हालांकि भवानीपुर से उन्होंने जीत हासिल की थी। इस बार यहां मुकाबला अहम है। क्योंकि भाजपा ने इस बार नंदीग्राम के साथ भवानीपुर से भी शुभेंदु अधिकारी को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या नंदीग्राम में ममता को हराने वाले शुभेंदु ममता के गढ़ में उनको हरा पाएंगे या फिर भाजपा का ये दांव शुभेंदु को ही उलटा पड़ जाएगा।

किन-किन नेताओं को मिला टिकट?

तृणमूल कांग्रेस की सूची में कई प्रमुख नेताओं को टिकट दिया गया है। सिलिगुड़ी से गौतम देव को उम्मीदवार बनाया गया है। रायगंज से कृष्ण कल्याणी, सागरदिघी से बायरन बिस्वास और चोपड़ा से हामिदुल रहमान को टिकट मिला है। इस्लामपुर से कन्हैयालाल अग्रवाल और हेमताबाद से सत्यजीत बर्मन को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा बालुरघाट से अर्पिता घोष और हरिरामपुर से बिप्लब मित्रा को उम्मीदवार बनाया गया है।

उत्तर बंगाल के कई जिलों में भी तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। मालतीपुर से अब्दुर रहीम बख्शी, इंग्लिशबाजार से आशीष कुंडू और सुजापुर से सबीना यास्मीन को टिकट मिला है। जंगीपुर से जाकिर हुसैन और मुर्शिदाबाद से सायनी सिंह रॉय को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा खग्राम से आशीष मरजित और कांडी से अपूर्व सरकार को मैदान में उतारा गया है। इस दौरान ममता ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के पक्ष में अच्छा खेल रहा है।

जेडीयू से अलग हुए पूर्व राज्यसभा सांसद केसी त्यागी

करीब दो दशकों से जेडीयू से जुड़े थे त्यागी

नई दिल्ली। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद केसी त्यागी ने पार्टी छोड़ने का एलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार उन्होंने पार्टी की सदस्यता नवीनीकरण नहीं कराया और अब वह आगे की राजनीतिक दिशा जल्द तय करेंगे। करीब दो दशकों से जेडीयू से जुड़े त्यागी का यह कदम बिहार और राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद केसी त्यागी ने पार्टी छोड़ने का एलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार उन्होंने पार्टी की सदस्यता नवीनीकरण नहीं कराया और अब वह आगे की राजनीतिक दिशा जल्द तय करेंगे। करीब दो दशकों से जेडीयू से जुड़े त्यागी का यह कदम बिहार और राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। केसी त्यागी ने साफ कहा कि वह जेडीयू से अलग हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी का सदस्यता अभियान समाप्त हो गया है और इस बार उन्होंने अपनी सदस्यता नवीनीकरण नहीं कराया। त्यागी ने कहा कि वह जल्द ही अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर फैसला करेंगे और इसके लिए अपने साथियों व समर्थकों से चर्चा करेंगे।

जेडीयू से कब से जुड़े थे केसी त्यागी?

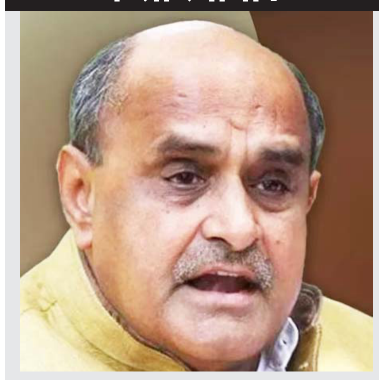

केसी त्यागी जेडीयू के गठन के समय से ही पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। अक्टूबर 2003 में समता पार्टी और जनता दल के विलय से जेडीयू का गठन हुआ था। तब से लेकर अब तक वह पार्टी के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे। उन्होंने पार्टी में मुख्य महासचिव, मुख्य प्रवक्ता और राजनीतिक सलाहकार जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। पार्टी छोड़ने के बावजूद केसी त्यागी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति सम्मान जताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ उनका करीब आधी सदी पुराना संबंध रहा है और उनके प्रति उनका व्यक्तिगत सम्मान पहले की तरह ही बना रहेगा।

आगे क्या होगी त्यागी की रणनीति?

केसी त्यागी ने कहा कि वह जल्द ही अपने राजनीतिक भविष्य पर फैसला करेंगे। उन्होंने बताया कि 22 मार्च 2026 को दिल्ली के रफी मार्ग स्थित मावलांकर हॉल में समान विचारधारा वाले लोगों की बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा होगी और आगे की दिशा तय की जाएगी।

न्यूज़ ब्रीफ

बिना सत्यापन वाले एलपीजी ग्राहकों के लिए ही 'आधार ई-केवाईसी' जरूरी

नई दिल्ली। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी (पहचान सत्यापन) जरूरी है, लेकिन यह नियम केवल उन्हीं ग्राहकों पर लागू होगा, जिन्होंने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है। सोशल मीडिया पर फैले भ्रम के बाद मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि सभी एलपीजी ग्राहकों को आधार ई-केवाईसी करनी होगी। इसके बिना गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, जिसे लेकर लोगों में हड़बड़ी फैल गई है। मंत्रालय ने साफ किया है कि यह कोई नया नियम नहीं है।

एयर होस्टेस से छेड़छाड़ के आरोप में भारतीय गिरफ्तार

सिंगापुर। सिंगापुर में एयर होस्टेस से छेड़छाड़ और उत्पीड़न के आरोप में भारतीय नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार, 35 वर्षीय आकाश तिवारी पर सिंगापुर एयरलाइंस की बैंकॉक से सिंगापुर जा रही उड़ान में महिला कर्मचारी को अनुचित तरीके से छूने का आरोप है।घटना नौ फरवरी की है। विमान के सिंगापुर पहुंचने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी। दोषी पाए जाने पर आरोपी को तीन साल तक की जेल, जुर्माना या अन्य सजा हो सकती है।

समान नागरिक संहिता पर ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार

गांधीनगर। गुजरात सरकार द्वारा गठित पांच सदस्यीय समिति ने अपनी विस्तृत और अंतिम ड्राफ्ट रिपोर्ट मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सौंप दी। यह रिपोर्ट राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए तैयार की गई है। सरकारी बयान के अनुसार, रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय समिति ने बताया कि इसमें सभी धर्मों और समुदायों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में एक समान कानूनी ढांचा प्रस्तावित किया गया है।

एंटनी राजू की याचिका खारिज

नई दिल्ली। केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व परिवहन मंत्री एंटनी राजू की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने साक्ष्य से छेड़छाड़ के मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। यह याचिका आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति पाने के उद्देश्य से दाखिल की गई थी। न्यायमूर्ति सी. जयचंद्रन ने राजू की याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि फिलहाल उनकी सजा बरकरार रहेगी।

वजन घटाने का 'शॉर्टकट' पड़ सकता है भारी

जल्दी मोटापा घटाने की चाहत से नकली दवाओं का कारोबार तेज, 60 देशों में फैला जाल

नई दिल्ली/मेक्सिको। मोटापा घटाने की चाहत और सोशल मीडिया पर दवाओं के प्रचार ने एक नए किस्म के स्वास्थ्य संकट को जन्म दे दिया है। बाजार में ओजेंपिक और माउनजारो जैसी प्रसिद्ध दवाओं के नाम पर नकली और असुरक्षित इंजेक्शन धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के लगभग 60 देशों में नकली वजन घटाने वाली दवाओं के फैलते कारोबार पर चिंता जताई है। बीमा कवर की कमी और दवाओं की असली कीमत बहुत ज्यादा होने के कारण लोग इंटरनेट या सस्ती दुकानों से ये दवाएं खरीद रहे हैं, जो सीधे तौर पर मौत को बुलावा देना है।

अमेरिका की संस्था 'पार्टनरशिप फॉर सेफ मेडिसिन्स' के अनुसार, ये नकली इंजेक्शन और दवाएं इतनी बारीकी से बनाई जाती हैं कि एक आम आदमी के लिए असली और नकली का फर्क करना मुश्किल है। इनमें अक्सर दवाओं के सक्रिय घटक होते ही नहीं, या फिर बेहद घटिया दर्जे के होते हैं।

सेहत पर दोहरी मार

इन नकली दवाओं में या तो हानिकारक तत्व होते हैं या फिर गलत खुराक। इससे शरीर में हाइपरग्लाइसीमिया (ब्लड शुगर का अत्यधिक बढ़ना) और हृदय संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। जल्दी वजन घटाने के चक्कर में लोग अपने दिल और किडनी को हमेशा के लिए नुकसान पहुँचा रहे हैं। 'द लैंसेट' की रिपोर्ट के अनुसार, मेक्सिको और अमेरिका की सीमाओं पर स्थित फार्मेसियों में ये दवाएं किसी चॉकलेट की तरह खुलेआम बेची जा रही हैं। पर्यटक और स्थानीय लोग बिना किसी पर्चे के इन्हें खरीद रहे हैं, जो एक बड़े अंतरराष्ट्रीय स्कैम की ओर इशारा करता है। डॉक्टरों और विशेषज्ञों का साफ कहना है कि मोटापा घटाना एक क्रमिक प्रक्रिया है। बिना मेडिकल सुपरविजन के 'वजन घटाने वाले जादुई इंजेक्शन' लेना शरीर के अंगों को फेल कर सकता है।

मातृत्व का हक और अधिकार बराबर

तीन माह से बड़े बच्चों को गोद लेने वाली महिलाओं को भी मिलेगा मैटरनिटी लीव

एजेंसी | नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को गोद लेने वाली माताओं के हक में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कर दिया है कि मातृत्व का सुख और जिम्मेदारी चाहे जैविक हो या गोद ली हुई, दोनों ही स्थितियों में माताओं के अधिकार एक समान हैं। पहले के नियमों (सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020) के अनुसार, केवल उन्हीं माताओं को 12 हफ्ते की छुट्टी मिलती थी, जो 3 महीने से छोटे बच्चे को गोद लेती थीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस सीमा को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब बच्चा चाहे किसी भी उम्र का हो, गोद लेने वाली मां को पूरे 12 हफ्ते का मातृत्व अवकाश मिलेगा। अदालत ने कहा कि पुराने नियम संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का उल्लंघन करते थे।

देश के 204 पूर्व सैनिक-अफसर नाराज

संसद में व्यवहार को लेकर राहुल गांधी से माफी की मांग

एजेंसी | नई दिल्ली

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक बार फिर विवादों के केंद्र में हैं। देश के 204 प्रबुद्ध नागरिकों, जिनमें पूर्व सैन्य अधिकारी, रिटायर्ड राजनयिक और वरिष्ठ वकील शामिल हैं, ने एक साझा पत्र जारी कर उनके व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई है। इन दिग्गजों ने राहुल गांधी से सार्वजनिक माफी की मांग की है। पूरा मामला 12 मार्च 2026 का है, जब राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया था। पूर्व अधिकारियों का कहना है कि लोकसभा स्पीकर ने पहले ही परिसर में किसी भी तरह के धरने या प्रदर्शन पर रोक लगा रखी थी, ऐसे में यह विरोध प्रदर्शन 'जानबूझकर की गई अवज्ञा' है।

'चाय-बिस्किट' वाले प्रदर्शन पर जताई आपत्ति

पत्र में विशेष रूप से इस बात का जिक्र किया गया है कि राहुल गांधी और अन्य सांसद संसद की सीढ़ियों पर बैठकर चाय-बिस्किट का सेवन करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। पूर्व सैन्य अधिकारियों का मानना है कि यह व्यवहार संसद के स्तर और गरिमा के अनुकूल नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद केवल बहस और कानून बनाने का मंच है, पिकनिक या राजनीतिक सर्कस का स्थान नहीं।

नियमों के उल्लंघन का लगाया आरोप

हस्ताक्षर करने वाले दिग्गजों ने संसद को 'लोकतंत्र का मंदिर' बताते हुए कहा कि इसकी पवित्रता केवल सदन के अंदर ही नहीं, बल्कि गलियारों और सीढ़ियों पर भी बनी रहनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यक्तिगत राजनीति चमकाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा को ताक पर रखा जा रहा है, जो जनता के बीच गलत संदेश भेजता है। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि राहुल गांधी अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। इस नाते उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उनका व्यवहार अनुकरणीय होना चाहिए, न कि ऐसा जिससे अराजकता का संदेश जाए। बार-बार होने वाले हंगामे से जनता का पैसा और समय दोनों बर्बाद हो रहे हैं। अंत में, इन 204 गणमान्य व्यक्तियों ने राहुल गांधी से मांग की है कि वे देश से माफी मांगें और अपने व्यवहार पर आत्ममंथन करें। उनका कहना है कि संसद की विश्वसनीयता बनाए रखना सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों की साझा जिम्मेदारी है।

विधानसभा चुनाव की तैयारी

निर्वाचन आयोग ने तैनात किए 1111 पर्यवेक्षक

नई दिल्ली। देश के चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में अगले महीने विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस चुनाव के चलते तेज होती राजनीति के बीच अब चुनाव आयोग ने भी बड़ा एलान किया है। आयोग ने बताया कि अगले महीने होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में उपचुनाव के लिए 1,111 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। बता दें कि इस बार विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में होने हैं। इसके अलावा कई राज्यों में अप्रैल में विधानसभा उपचुनाव भी आयोजित होंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि ये पर्यवेक्षक चुनाव के दौरान आंख और कान की तरह काम करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव मुक्त और निष्पक्ष तरीके से हों।

इंसाफ के घर देर है, अंधेर नहीं

ऊना में दलितों की पिटाई के मामले में आठ साल बाद कोर्ट का फैसला

ऊना। गुजरात के ऊना में चार दलितों को साल 2016 में सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने के मामले में एक विशेष अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने पांच दोषियों को पांच साल की सजा सुनाई है और प्रत्येक दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इन दलितों को उस समय पीटा गया था, जब वे कथित रूप से एक मरी हुई गाय की खाल उतारने की कोशिश कर रहे थे। वेरावल की विशेष अदालत ने इस मामले में सोमवार को पांच लोगों को दोषी ठहराया था। वहीं, 35 लोगों को बरी कर दिया गया था। इस घटना के समय देशभर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे।

शबीर शाह को सुप्रीम कोर्ट से राहत

टेरर फंडिंग केस में मिली सशर्त जमानत

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी राजनीति का एक बड़ा चेहरा माने जाने वाले शबीर अहमद शाह को सुप्रीम कोर्ट ने 'टेरर फंडिंग' (आतंकी वित्तपोषण) के मामले में जमानत दे दी है। करीब 7 साल से जेल में बंद शाह को अदालत ने उनकी उम्र और मुकदमे में हो रही देरी को देखते हुए राहत दी है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि शबीर शाह जून 2019 से लगातार हिरासत में हैं। उनकी उम्र 74 वर्ष हो चुकी है और मुकदमे (Trial) की रफ्तार बहुत धीमी है। अदालत का मानना है कि यदि सुनवाई जल्दी पूरी होने की उम्मीद न हो, तो किसी को अनिश्चित काल तक जेल में रखना उसकी व्यक्तिगत आजादी के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है।

दिल्ली में ही रहना होगा

अदालत ने जमानत तो दी है, लेकिन शाह की आवाजाही पर कड़ा पहरा बिठाया है। उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करना होगा ताकि वे देश छोड़कर न जा सकें। शबीर शाह केवल एक मोबाइल या लैंडलाइन नंबर का ही उपयोग कर पाएंगे। उन्हें अपना फोन 24 घंटे चालू रखना होगा ताकि जांच एजेंसियां उन तक पहुँच सकें।

संसद डायरी | 59 फैसलों में से 56 में आरोपी पाए गए दोषी

मनी लॉन्ड्रिंग पर ईडी का 'स्ट्राइक रेट' हाई

5 साल में 124 लोगों को मिली सजा

राज्यसभा में सरकार ने पेश किए आंकड़ें

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय की पिछले पांच वर्षों की कार्रवाई को लेकर मंगलवार, 17 मार्च 2026 को संसद में महत्वपूर्ण आंकड़े पेश किए गए। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत अदालतों में दोषसिद्धि की दर काफी प्रभावी रही है। 1 अप्रैल, 2021 से 28 फरवरी, 2026 के बीच विशेष अदालतों ने कुल 59 मामलों में अपने फैसले सुनाए। इनमें से 56 मामलों में आरोपियों को सजा मिली, यानी लगभग 95% मामलों में ईडी अपने आरोप साबित करने में सफल रही। इस दौरान कुल 124 आरोपियों को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराया गया।

ईडी की रडार पर 4,377 नए केस

वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में ईडी ने कुल 4,377 ECIR (एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट) दर्ज की हैं। इसी अवधि के दौरान PMLA के सख्त प्रावधानों के तहत 903 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह आंकड़ा आर्थिक अपराधों के खिलाफ सरकार की सक्रियता को दर्शाता है।

1,245 मामलों में दाखिल की गई चार्जशीट

ईडी ने अब तक 1,245 मामलों में विशेष अदालतों के सामने आरोप-पत्र (चार्जशीट) दाखिल किए हैं। इनमें न केवल आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की गई है, बल्कि अपराध से अर्जित काली कमाई और संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

93 मामलों में फाइल हुई क्लोजर रिपोर्ट

2019 के संशोधन के बाद, जिन मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध नहीं बनता, उनमें ईडी को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करना अनिवार्य है। सरकार ने बताया कि अब तक 93 मामलों में क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई है। ऐसा तब होता है जब मुख्य अपराध रद्द हो जाता है या कोर्ट को शेड्यूल अपराध से जुड़ा कोई सबूत नहीं मिलता। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ मामलों में आरोपी बरी हुए हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण ईडी की जांच नहीं, बल्कि 'शेड्यूल अपराध' के मामले में आरोपी का बरी होना या आरोपमुक्त होना रहा है।